रांची से प्रकाशित लोकप्रिय दैनिक

अलग पहचान

सत्य की उड़ान

शुक्रवार
11 सितंबर -2026
वर्ष 11, अंक 03
पेज 8, मूल्य 2 रुपए
रांची

गणेश चतुर्थी, करम पर्व, दुर्गापूजा, दीपावली, छठ एवं काली पूजा को लेकर विभागीय पदाधिकारियों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

पूजा पंडालों के निर्माण से लेकर विसर्जन तक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश

● आगामी पर्व-त्यौहारों के सफल एवं सुरक्षित आयोजन को लेकर बैठक

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची / रांची। आगामी पर्व-त्यौहारों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में गणेश चतुर्थी, करम पर्व, दुर्गापूजा, दीपावली, छठ एवं काली पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, विसर्जन व्यवस्था एवं आमजनों की सुविधा को लेकर विस्तृत समीक्षा की गयी।

बैठक में पुलिस अधीक्षक, नगर पारस राणा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गौरव गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक यातायात राकेश सिंह, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर कुमार रजत, प्रशिक्षु आईएएस (IAS Probationer) आस्था शरण, अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि-व्यवस्था) धनंजय, नजारत उपसमाहर्त्ता सुदेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पाण्डेय सहित बिजली विभाग, नगर निगम, अग्निशमन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि पर्व-त्यौहारों का आयोजन श्रद्धा एवं उत्साह के साथ हो, लेकिन इसके साथ सुरक्षा मानकों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को पूजा समितियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आयोजन से पूर्व आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच करने तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिये।

पंडाल निर्माण में सुरक्षा मानकों के अनुपालन का निर्देश

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी पूजा समितियों द्वारा पंडाल निर्माण के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पंडाल का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि श्रद्धालुओं के आवागमन

में किसी प्रकार की बाधा न हो तथा आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता उपलब्ध रहे। उन्होंने अग्निशमन विभाग के पदाधिकारियों को पंडालों का निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा मानकों की जांच करने के निर्देश दिये। पंडाल में प्रवेश एवं निकास मार्ग, आपातकालीन निकासी, विद्युत वायरिंग तथा अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिजली के खंभे, ट्रांसफॉर्मर अथवा अन्य विद्युत संरचनाओं से सटाकर पंडाल या तोरण द्वार का निर्माण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। बिजली विभाग के पदाधिकारियों को पूजा समितियों के साथ समन्वय कर इसका विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

विद्युत सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता

पंडालों एवं पूजा स्थलों में विद्युत व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। पूजा समितियों को आवश्यकतानुसार बिजली विभाग से निर्धारित प्रक्रिया के तहत विद्युत कनेक्शन एवं स्वीकृत लोड लेने के लिए कहा गया।

डेकोरेशन एवं रोशनी के लिए नंगे तारों का उपयोग नहीं करने, खुले एवं असुरक्षित विद्युत तारों को तत्काल हटाने तथा सभी वायरिंग को सुरक्षित तरीके से करने का निर्देश दिया गया। विद्युत तारों एवं कनेक्शन की नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि शॉर्ट सर्किट अथवा विद्युत दुर्घटना की संभावना को न्यूनतम किया जा सके।

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि बिजली विभाग के पदाधिकारी क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करें और यदि कहीं भी विद्युत सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें।

विसर्जन के दौरान सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था पर विशेष जोर

विसर्जन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने निर्देश दिया कि सभी पूजा समितियां संबंधित थाना एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पूर्व निर्धारित विसर्जन रूट का ही उपयोग करें। विसर्जन के दौरान भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया।

उन्होंने विसर्जन में उपयोग किये जाने वाले वाहनों की एमवीआई से जांच कराने का निर्देश दिया। साथ ही वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच तथा नो-एल्कोहोल टेस्ट सुनिश्चित कराने को कहा गया। इस संबंध में पूजा समितियों से आवश्यक अंडरटेकिंग लेने का निर्देश भी दिया गया।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश

पंडालों में आग लगने की किसी भी संभावित घटना को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग को सभी प्रमुख पूजा स्थलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। पंडालों में आवश्यकतानुसार अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, विद्युत वायरिंग की स्थिति तथा आपातकालीन निकासी व्यवस्था की जांच करने को कहा गया। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने निर्देश दिया कि पूजा समितियों के पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को भी प्राथमिक अग्नि सुरक्षा एवं आपात स्थिति में भीड़ को नियंत्रित करने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जाए।

संक्षिप्त समाचार

चीनी राष्ट्रपति का गलवान झड़प के बाद पहला भारत दौरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। अगर यह बैठक होती है तो जून 2020 में हुई गलवान हिंसा के बाद दोनों नेताओं की भारत में पहली द्विपक्षीय बातचीत होगी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे।

रेलवे टेंडर घोटाला

लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी समेत 9 के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप तय

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने लालू यादव के दामाद राहुल यादव समेत सात लोगों को बरी करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने इन तीनों के अलावा जिनके खिलाफ आरोप तय किया है, उनमें लारा प्रोजेक्ट्स, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, सुजाता होटल्स, विनय कोचर और विजय कोचर शामिल हैं. कोर्ट ने जिन लोगों को बरी करने का आदेश दिया है।

सीएम योगी का ऐलान

यूपी की एक करोड़ दीदियों को मिलेगा एक लाख तक का ब्याज मुक्त लोन

लखनऊ (एजेंसी)। विधान सभा चुनाव से पहले महिलाओं को लुभाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट योजना में महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं एक करोड़ दीदियों को एक लाख रुपये तक का क्रेडिट (ऋण) लाभ दिया जाएगा। हालांकि योजना के पहले चरण में 20,000 रुपये की पहली किश्त मिलेगी।

इसके समय से भुगतान पर दो चरणों में 80 हजार रुपये का और क्रेडिट दिया जाएगा। सरकार, योजना को विधान सभा चुनाव से पहले जोर-शोर से लांच करने की तैयारी कर रही है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है : पीएम मोदी

2035 तक अपना स्पेस स्टेशन होगा और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय होंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार, 10 सितंबर को पेरिस में इंटरनेशनल स्पेस समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ स्पेस डोमेन का समर्थन करता है। स्पेस की संभावनाएं असीमित हैं और हमारी जिम्मेदारी सामूहिक है।

स्पेस के क्षेत्र में कीर्तिमान रच रहा भारत- प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेस में भारत की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए कहा, चंद्रयान-3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना दिया है। आदित्य L1 सूरज के रहस्यों को उजागर कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) की टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया के काम आती हैं। इस वैश्विक भरोसे के पीछे भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों की कई पीढ़ियों का समर्पण और कड़ी मेहनत है। दिन-रात काम करके उन्होंने ISRO की प्रतिष्ठा बनाई है। प्रधानमंत्री ने स्पेस में भारत के भविष्य को लेकर कहा, पिछले साल, एक भारतीय ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा किया। आगे देखते हुए, हमारा लक्ष्य 2035 तक एक भारतीय स्पेस स्टेशन स्थापित करना और 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है।

जयपुर में रनवे छूते ही फिर आसमान में उड़ा विमान,43 यात्री थे सवार

जयपुर (एजेंसी)। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार दोपहर इंडिगो की एक फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान अचानक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। उदयपुर से जयपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-7516 ने जैसे ही जयपुर रनवे पर टचडाउन किया, पायलट ने अचानक लैंडिंग एबॉर्ट (निरस्त) कर दी और विमान को तुरंत दोबारा हवा में उठा लिया। टचडाउन के ठीक बाद अचानक विमान के वापस टेकऑफ करने से उसमें सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सांसें थम गईं।

39 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स समेत कुल 43 लोग थे सवार- घटना दोपहर लगभग 12.42 बजे की है, जब फ्लाइट अपने निर्धारित समय (दोपहर 12.50 बजे) से कुछ मिनट पहले लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रही थी। विमान रनवे को छू चुका था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इस पल में पायलट ने 'गो-अराउंड' का फैसला लिया। उस समय विमान में 39 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स समेत कुल 43 लोग सवार थे।

सागर में 29 मौतों के बाद बुलडोजर एक्शन

● जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपितों के घर पहुंचा प्रशासन

सागर (एजेंसी)। सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब पीने से 29 लोगों की मौत के बाद सरकार और प्रशासन ने अब आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध शराब के इस जानलेवा कारोबार से जुड़े मुख्य आरोपितों के घरों तक गुरुवार को प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया। राजस्व और पुलिस बल की भारी मौजूदगी के बीच प्रशासनिक टीम आबकारी ठेकेदार एवं मुख्य आरोपित मनीष लोधी उर्फ यशवंत सिंह ठाकुर के बंडा स्थित घर पहुंची। वहीं ततरवारा सरपंच चंद्रभान उर्फ चंदू सिंह राजपूत के मकान पर भी कार्रवाई के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा।

नगर परिषद बंडा और राजस्व विभाग की टीम ने बीते दो दिनों में दोनों आरोपितों के मकानों का सीमांकन और नपती कराई थी।

मुख्य आरोपित पर 20 हजार का इनाम

पुलिस के मुताबिक मनीष लोधी उर्फ यशवंत सिंह ठाकुर नई शराब की खेप तैयार होने के बाद बिहार चला गया था। वहां से लौटते समय सतना पहुंचने पर उसे जहरीली शराब से हो रही मौतों की जानकारी मिली। इसके बाद वह वहीं से फरार हो गया।

मक्के के खेत में चल रही थी मौत की फैक्ट्री

पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस जहरीली शराब ने 29 लोगों की जान ली, उसकी करीब 50 पेटियां ततरवारा गांव में मक्के के खेत के भीतर संचालित अवैध फैक्ट्री में तैयार की गई थीं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार चंदू राजपूत का संपर्क बरेठी शराब दुकान के लाइसेंसधारी मनीष लोधी से था। वहीं मनीष लोधी के तार अंतरराज्यीय शराब तस्कर रवि लखेरा से जुड़े थे। रवि लखेरा वही आरोपित बताया जा रहा है, जिसे चार मई 2026 को उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुलिस ने नकली शराब की फैक्ट्री संचालित करने के आरोप में पकड़ा था।

बिहार के 14 जिलों में बाढ़, 5 हजार स्कूल बंद

यूपी के बाराबंकी में घर बहे, बरेली में मंदिर डूबा, मप्र-राजस्थान में बारिश थमी

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार में पटना, मुंगेर और भागलपुर समेत 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। पांच हजार से ज्यादा स्कूल बाढ़ में डूबने के चलते बंद किए गए हैं।

राज्य में गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियां उफान पर हैं। इनके किनारे के 500 से ज्यादा श्मशान घाट डूबे हैं, जिसके चलते अंतिम संस्कार करने में परेशानी हो रही है। यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। यहां 26 जिलों में बाढ़ से 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बरेली में प्राचीन मंदिर रामगंगा नदी में समा गया। बाराबंकी में सरयू के पानी में करीब 12 मकान डूब गए।

इधर, एमपी और राजस्थान में फिलहाल बारिश का दौर थमा हुआ है। एमपी में अगले 3 दिन तेज बारिश

की संभावना नहीं है। राजस्थान में 11 सितंबर से बारिश शुरू होने का अनुमान है। बुधवार को यहां 10 शहरों में तापमान 35 डिग्री से ऊपर रहा।

एमपी: मानसून कमजोर, तेज बारिश का दौर थमा

मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश का कोई सक्रिय सिस्टम नहीं है, जिसके चलते तेज बारिश का दौर थम गया है।

राजस्थान: आज से फिर बारिश का दौर, 10 शहरों में पारा 35 डिग्री पार- मौसम विभाग ने राजस्थान में 11 सितंबर से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। शुक्रवार को 5 जिलों में तेज बारिश का यलो अलर्ट है। इसके बाद 12 और 13 सितंबर को भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के इलाकों में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

साहित्य अकादेमी ने प्रख्यात ओड़िया लेखिका प्रतिभा राय को फेलोशिप प्रदान की

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /भुवनेश्वर। उड़िया।

साहित्य अकादेमी ने प्रख्यात ओड़िया लेखिका एवं विदुषी डॉ. प्रतिभा राय को आज भुवनेश्वर के संस्कृति भवन सभागार में आयोजित एक विशेष समारोह में साहित्य अकादेमी फेलोशिप से सम्मानित किया।

समारोह का शुभारंभ डॉ. अद्याशा दास द्वारा प्रस्तुत मंगलाचरण गीत से हुआ। साहित्य अकादेमी के सचिव डॉ. वरुण गुलाटी ने स्वागत वक्तव्य दिया और डॉ. प्रतिभा राय को प्रदान की जाने वाली फेलोशिप का प्रशस्ति-पत्र पढ़कर सुनाया।

साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष डॉ. माधव कौशिक ने डॉ. प्रतिभा राय को फेलोशिप की पट्टिका प्रदान की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने डॉ. राय को 'भारतीय साहित्य की जीवंत किंवदंती' बताते हुए उनके

साहित्यिक योगदान की सराहना की।

इस अवसर पर एक विशेष 'संवाद' कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसके पश्चात फेलोशिप प्रदान करने का औपचारिक समारोह हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉ. गौरहरि दास ने की। उन्होंने कहा कि डॉ. प्रतिभा राय ओडिशा की पहली महिला लेखिका हैं, जिन्हें साहित्य अकादेमी की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है।

समारोह में प्रख्यात लेखक देबप्रसाद दास, प्रोफेसर संघमित्रा मिश्रा तथा प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार महंती ने डॉ. प्रतिभा राय के जीवन, व्यक्तित्व और साहित्यिक कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त किए तथा भारतीय साहित्य में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया।

इस अवसर पर डॉ. प्रतिभा राय ने साहित्य अकादेमी की फेलोशिप प्राप्त करने पर अपना स्वीकृति वक्तव्य दिया।

कार्यक्रम के अंत में साहित्य अकादेमी के उप सचिव डॉ. एन. सुरेश बाबु ने धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह में बड़ी संख्या में साहित्यकार, लेखक, विद्वान और साहित्यप्रेमी उपस्थित थे।

अमेरिकी रिपोर्ट में भारत के परमाणु भंडार पर बड़ा खुलासा

ताकत जानकर दुनिया के कई देश अवाक

नईदिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका के एक गैर लाभकारी विचार समूह के अनुसार, भारत के परमाणु जखीरे में 190 आयुध होने का अनुमान है, जिनमें वर्तमान में निर्मित की जा रही नयी

● भारत ने 140 से लेकर 225 परमाणु आयुध तक के लिए पर्याप्त सैन्य प्लूटोनियम का उत्पादन किया

मिसाइलों के लिए 30 अतिरिक्त परमाणु आयुध भी शामिल हैं। 'फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स' (एफएएस) ने ये अनुमान खुले स्रोत, सरकारी डेटा और वाणिज्यिक उपग्रहों से ली गई तस्वीरों के विश्लेषण के आधार पर

लगाए हैं। एफएएस परमाणु सूचना परियोजना के निदेशक हैंस क्रिस्टेंसन के लेख 'इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स-2026' के अनुसार, परमाणु आयुध से मिसाइल को लैस करने की भारत की क्षमता और रणनीति के बारे में उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर, हमारा अनुमान है कि भारत ने लगभग 190 परमाणु आयुध बनाए होंगे। इसमें कहा गया है कि भारत के परमाणु आयुध भंडार में लॉन्चर के लिए 160 से अधिक आयुध और निर्मित हो रही नयी मिसाइलों के लिए अतिरिक्त आयुध शामिल हैं। बुधवार को प्रकाशित एक आलेख में बताया गया है कि भारत अपने परमाणु आयुध के जखीरे को आधुनिक बनाने का काम जारी रखे हुए है।

संक्षिप्त समाचार

साइबर थाना में एसीबी की दबिश, अवर निरीक्षक पुनित कुमार गौतम गिरफ्तार

गिरिडीह, एजेंसी। साइबर थाना में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की दबिश पड़ी है। बरवाडीह स्थित साइबर थाना में पदास्थापित पुलिस अवर निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अवर निरीक्षक पुनित कुमार गौतम है। पुनित को धनबाद साइबर की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी बुधवार की दोपहर लगभग 12 बजे हुई है। गिरफ्तारी के बाद अवर निरीक्षक को अपने साथ लेकर एसीबी धनबाद चली गई। गिरफ्तारी की पुष्टि एसीबी धनबाद ने की है।

खूंटी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग, पीएलएफआई के नाम पर 10 लाख की लेवी मांगी, दो नकाबपोश अपराधी फरार

रांची/खूंटी, एजेंसी। जिले में हथियारबंद अपराधियों ने बुधवार देर रात शहर के बीचों-बीच भगत सिंह चौक स्थित व्यवसायी और संवेदक अमित साहू के पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर दहशत फैला दी। बाइक से पहुंचे दो नकाबपोश अपराधियों ने पंप परिसर में एक राउंड गोली चलाई और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम से पर्चा फेंककर तोरपा रोड की ओर फरार हो गए। घटना के बाद पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मियों और ग्राहकों के बीच अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, गोली किसी को नहीं लगी। घटना बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे की बताई जा रही है। वारदात के समय पेट्रोल पंप संचालक अमित साहू मौके पर मौजूद नहीं थे। अपराधियों द्वारा छोड़े गए पर्चे में पीएलएफआई के जोनल कमांडर राजेश यादव के नाम का उल्लेख करते हुए दो दिनों के भीतर संगठन को सहयोग राशि के रूप में 10 लाख रुपये पहुंचाने का फरमान दिया गया है। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। फायरिंग की सूचना मिलते ही एसडीपीओ मंगल सिंह जमुदा और सदर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच करते हुए एक खोखा और पीएलएफआई के नाम से फेंका गया पर्चा बरामद किया है। साथ ही सीसीटीवी की जांच की। सीसीटीवी कैमरों में दोनों अपराधी गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने अपने चेहरे गमछे से ढक रखे थे।

रेलवे कॉलोनी के पास मिला नवजात शिशु, जांच शुरू

रांची, एजेंसी। राजधानी रांची रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी में गुरुवार को कपड़े में लिपटा एक नवजात शिशु मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। मात्र कुछ दिनों के ही नवजात को किसी ने कपड़े में लपेटकर जिंदगी और मौत के बीच छोड़ दिया था। स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया है। गुरुवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक युवक ने कॉलोनी में बच्चे के रोने की आवाज सुनी। युवक ने पास जाकर देखा तो कपड़े में लिपटा एक नवजात दिखाई दिया। युवक ने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस जगह बच्चे को छोड़ा गया था, वहां अक्सर आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। ऐसे में समय रहते बच्चे के मिल जाने से उसकी जान बच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। नवजात को सुरक्षित कब्जे में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। चुटिया थाना प्रभारी पूनम कुजूर ने बताया कि सीडब्ल्यूसी (बाल कल्याण समिति) की ओर से थाने को नवजात बरामद होने की सूचना दी गई है। फिलहाल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। नवजात को वहां कौन छोड़कर गया, पुलिस इसकी जानकारी जुटा रही है। इसके लिए आसपास के इलाकों और रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी के प्रवेश और निकास मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इसके अलावा आसपास के अस्पतालों और नर्सिंग होम से भी हाल के दिनों में हुए प्रसव की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर रही है।

रांची जिला बल में भारी बदलाव, 459 पुलिसकर्मियों का तबादला, 68 महिलाएं भी शामिल

रांची, एजेंसी। रांची जिला पुलिस बल में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। एसएसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार कुल 459 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। इनमें 391 पुरुष और 68 महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। एसएसपी कार्यालय रांची से दी गई जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मियों को वर्तमान तैनाती से हटाकर अलग-अलग थानों, ओपी, रिज़र्व गार्ड और पुलिस इकाइयों में पदस्थापित किया गया है। आदेश की सूची में दयानंद कुमार, संजीव कुमार, राकेश कुमार, अरुण कुमार, रवि कुमार, अमित कुमार, मनोज उरांव, राजेश कुमार, सुशील कुमार और विकास कुमार समेत कई पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। शुरुआती सूची में डीएपी श्रेणी के जवानों का तबादला किया गया है। इसी तरह आगे की सूची में राजेंद्र प्रसाद यादव, राजीव पी। सिंह, सुरेश कुमार, अजीत कुमार, नरेश कुमार और प्रकाश कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के नाम हैं। इन जवानों को अलग-अलग थाना रिजर्व गार्ड में भेजा गया है। वहीं, महिला पुलिसकर्मियों में अर्चना देवी, कविता देवी, प्रतिमा देवी, रंजना देवी, सुनीता कुमारी, पूनम देवी और अंजलि कुमारी समेत कई नाम शामिल हैं। महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी अलग-अलग थाना क्षेत्रों और पुलिस इकाइयों में की गई है। आदेश में डीएपी, एच डीएपी, एल डीएपी और ओआर श्रेणी के पुलिसकर्मी शामिल हैं। प्रत्येक नाम के सामने संबंधित पुलिसकर्मी की वर्तमान और नई पदस्थापना दी गई है। महिला पुलिसकर्मियों को विभिन्न थाना क्षेत्रों में भेजा गया है। इनमें महिला थाना, कोतवाली, सदर, डोरंडा, अरगोड़ा, जगन्नाथपुर समेत कई पुलिस प्रतिष्ठानों और थानों में पदस्थापन किया गया है।जारी आदेश में रांची के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों की तैनाती बदली गई है। कई जवानों को एक थाना रिजर्व गार्ड से दूसरे थाना रिजर्व गार्ड में भेजा गया है। वहीं, कुछ पुलिसकर्मियों का पदस्थापन पुलिस लाइन, यातायात, महिला थाना और अन्य पुलिस इकाइयों में किया गया है।

गुजरात की शेल पार्टियों को हजारों करोड़ के चंदे पर पर झामुमो ने उठाए सवाल!

कहा-कहां है चुनाव आयोग और जांच एजेंसियां

रांची, एजेंसी। गुजरात में चुनाव आयोग से पंजीकृत, लेकिन बगैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां को कथित तौर पर मिल रहे करोड़ों रुपये के चंदे को लेकर झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने गंभीर सवाल उठाए हैं। बुधवार को पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों की न तो स्पष्ट राजनीतिक गतिविधियां दिखाई देती हैं, न वे नियमित रूप से चुनाव लड़ती हैं और न ही उनके कार्यालयों की सक्रियता नजर आती है, उनके खातों में सैकड़ों करोड़ रुपये कैसे पहुंच रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए।

झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि यह मामला केवल गुजरात तक सीमित नहीं है। यदि किसी राजनीतिक दल के नाम पर भारी रकम का लेनदेन हो रहा है, तो उसके स्रोत, दानदाताओं और धन के इस्तेमाल की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। उन्होंने कागजों पर चल रहे ऐसी राजनीतिक पार्टियों की तुलना शेल कंपनियों से करते हुए कहा कि हैरत की बात यह है कि यह बेहद गंभीर मामला है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतने गंभीर मुद्दे पर चुनाव आयोग, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय जैसी संस्थाएं मौन क्यों हैं।

उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास पंजीकृत हैं। इनमें कुछ को राष्ट्रीय और कुछ को राज्यस्तरीय पार्टी की मान्यता प्राप्त है, जबकि बड़ी संख्या में दल Registered Unrecognised Political Parties के रूप में दर्ज हैं। चुनाव आयोग के 2024 एटलस के अनुसार देश में 2670 RUPPs दर्ज थी। RUPP होना अपने आप में किसी पार्टी को फर्जी या अवैध नहीं बनाती। यह केवल चुनाव आयोग की मान्यता की एक अलग श्रेणी है। किसी दल की वित्तीय या राजनीतिक गतिविधियों पर सवाल होने की स्थिति में उसके रिकॉर्ड की अलग से जांच जरूरी होती है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि गुजरात में सामने आए कुछ मामलों में कथित तौर पर ऐसी पार्टियों का जिक्र है जिनके अध्यक्ष, ट्रेजरर और कार्यालय की वास्तविक सक्रियता तक स्पष्ट नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी पार्टी का न अध्यक्ष स्पष्ट रूप से सामने है, न कोषाध्यक्ष

की गतिविधियां दिखाई देती हैं, न कार्यालय सक्रिय है, न राजनीतिक गतिविधियां और न ही पार्टी चुनाव लड़ती है, तो उसे इतना बड़ा चंदा कैसे मिल रहा है उन्होंने सवाल किया कि 'चंदा कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल कहां और कैसे हो रहा है' उनका कहना है कि यही वे सवाल हैं जिनका जवाब संबंधित जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग को तलाशना चाहिए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि गुजरात में ऐसी करीब 10 पार्टियां हैं, जिन्हें 2023-24 में बड़ी मात्रा में चंदा मिला। इनमें कुछ पार्टियों के खातों में कथित तौर पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक, किसी के खाते में करीब 620 करोड़ रुपये, किसी में करीब 900 करोड़ रुपये और एक अन्य पार्टी के खाते में करीब 138 करोड़ रुपये होने की बात कही गई। विनोद पांडेय ने लोकशाही सत्ता पार्टी का उदाहरण देते हुए दावा किया कि उसे 2023-24 में करीब 1,045 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। हालांकि इन आंकड़ों और संबंधित पार्टियों के वित्तीय रिकॉर्ड की स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित राजनीतिक दलों का पक्ष सामने आना जरूरी है। किसी राजनीतिक दल के खाते में बड़ी राशि होना अपने आप में अवैधता या मनी लॉन्ड्रिंग का प्रमाण नहीं है।

झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने सवाल उठाया कि कहीं इन राजनीतिक दलों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई संदेह है तो जांच एजेंसियों को इसकी तह तक जाना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि इन पार्टियों को चंदा देने वाले लोग या संस्थाएं कौन हैं। उन्होंने कहा कि कहीं देश में राजनीतिक दलों में टूट, विधायकों और सांसदों के पाला बदलने तथा खरीद-फरोख्त के आरोपों को लेकर लगातार राजनीतिक बहस होती रही है। ऐसे में यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि कहीं इन कथित भारी-भरकम फंड का इस्तेमाल किसी राजनीतिक गतिविधि या निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रभावित करने में तो नहीं हो रहा।

झामुमो नेता ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और आयकर विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाया। लेकिन यदि किसी राजनीतिक दल के खातों में इतनी बड़ी रकम होने की जानकारी सामने आ रही है तो संबंधित एजेंसियां इसकी पड़ताल क्यों नहीं करतींउन्होंने सवाल किया कि यदि किसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आधार सामने आता है तो श्वष्ठ इसे संज्ञान में क्यों नहीं लेती, आयकर विभाग इन चंदों और संबंधित वित्तीय लेनदेन की जांच क्यों नहीं करता उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि कहीं दूसरे दलों को तोड़ने, विधायकों-सांसदों की खरीद-बिक्री में इन्हीं राशि का तो खर्च नहीं हो रहा है उन्होंने कहा कि ऐसे में इन एजेंसियों का दायित्व है कि वे ऐसे मामलों को देखें, समझें और तथ्यों की जांच करें।

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में बवाल: कुलपति की शक्तियां जब्त, रजिस्ट्रार भी हटाए गए

पलामू, एजेंसी। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में बवाल मचा हुआ है। राज्यपाल ने नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को जब्त कर लिया है। वहीं, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ नफीस अहमद का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है। डॉ नफीस अहमद की जगह पर डॉ मृत्युंजय कुमार को प्रभारी रजिस्ट्रार बनाया गया है। डॉ मृत्युंजय कुमार यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर के पद पर तैनात है।

दरअसल, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति को लेकर राजभवन से पत्र आया था। पत्र के आलोक में रजिस्ट्रार ने भी एक पत्र जारी किया था। इस पत्र में लिखा गया है कुलपति दैनिक कार्यों के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में पहले लोकभवन से अनुमति प्राप्त करने होंगे। यानी राज्यपाल सह कुलाधिपति ने वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की बात कही है।

रजिस्ट्रार डॉ नफीस अहमद ने एक महीने पहले इस्तीफा दे दिया था और उनका इस्तीफा 10 सितंबर से लागू होना था। 9 सितंबर को डायरेक्टर हायर एजुकेशन के निर्देश पर कुलपति ने रजिस्ट्रार के पद पर डॉ मृत्युंजय कुमार को तैनात किया है। कुलपति और रजिस्ट्रार को लेकर 09 सितंबर को ही आदेश जारी हो गया था। पूरे मामले में कुलपति और रजिस्ट्रार फिलहाल कुछ भी नहीं बोलने को तैयार नहीं है। इधर, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में कथित वित्तीय गड़बड़ी को लेकर छात्र संगठनों का आंदोलन जारी है। सूचना के अधिकार कानून के तहत छात्र संगठन यूनिवर्सिटी का ऑडिट रिपोर्ट को निकाला था और प्रतिदिन मीडिया के सामने खुलासा कर रहे थे। छात्र संगठनों ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी।

रजिस्ट्रार के मामले में भी छात्र संगठन ने राज्यपाल को पत्र लिखा और मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया है। छात्र नेता राहुल दुबे ने बताया कि रजिस्ट्रार के मामले में भी राज्यपाल को पत्र लिखा गया है। जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अंतिम पायदान तक नहीं पहुंचती है, छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा।

एमओसीपी-16 में रैयतों की वार्ता बेनतीजा बीसीसीएल के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

धनबादः मुकुंदा ओपन कास्ट परियोजना एमओसीपी-16 से प्रभावित मौजा के रैयतों और बीसीसीएल प्रबंधन के बीच गुरुवार को बैलगड़िया टाउनशिप जेरेडा सभागार में आयोजित वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई। मुआवजा, नियोजन, पुनर्वास और गांव के विकास जैसे अहम मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन प्रबंधन द्वारा ठोस आश्वासन नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण बैठक से बाहर निकल गए।

ग्रामीणों ने कहा कि परियोजना के कारण उनकी कृषि भूमि, आवास और आजीविका पर गहरा असर पड़ा है और बिना उचित व्यवस्था के जमीन पर जबरन किसी भी तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान रैयतों ने प्रबंधन को अपनी पांच सूत्री मांगों से अवगत कराते हुए वर्तमान सरकारी दर से चार गुना मुआवजा, प्रभावित परिवारों को स्थायी नियोजन, विस्थापितों के लिए उपयुक्त पुनर्वास की जमीन, गांव के सर्वांगीण विकास और जेरेडा क्षेत्र में बनने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में मूल रैयतों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग रखी।

मुखिया मनोज सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन जबरन जेसीबी चलाकर जमीन लेने का प्रयास कर रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा।

मांगों का समाधान किए बिना यदि कार्य शुरू किया गया तो ग्रामीण लोकतांत्रिक तरीके से कड़ा विरोध करेंगे। बैठक में गौतम सिंह, मनोहर सिंह, अतुल सिंह, विकास चौधरी, अनिल मंडल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे, जिन्होंने चेतावनी दी कि शीघ्र निर्णय नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।

एशियन गेम्स में झारखंड की चार बेटियों पर नजर, सलीमा टेटे संभालेंगी भारतीय टीम की कमान

रांची, एजेंसी। एफआईएच महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पांचवां स्थान हासिल करने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम 20वें एशियन गेम्स आइची-नागोया 2026 के लिए जापान रवाना हो गई हैं।

एशियन गेम्स में भारतीय टीम की कमान झारखंड की स्टार और सिमडेगा की सलीमा टेटे संभाल रही हैं। टीम का लक्ष्य एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के साथ लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफिकेशन हासिल करना है।

भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की चार खिलाड़ियों को जगह मिली है। इनमें कप्तान सलीमा टेटे के अलावा खूंटी की निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और सिमडेगा की दीपिका सोरेंग शामिल हैं। चारों खिलाड़ियों के चयन से एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय हॉकी में झारखंड की प्रतिभा और मजबूत उपस्थिति सामने आई है। खास तौर पर सलीमा टेटे को भारतीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने से राज्य के खेल प्रेमियों में उत्साह है।

एशियन गेम्स के हॉकी मुकाबलों में भारत को पूल-बी में रखा गया है। इस पूल में भारत के साथ मेजबान जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान की टीमें हैं। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 20 सितंबर को उज्बेकिस्तान के खिलाफ करेगी। इसके बाद 21 सितंबर को इंडोनेशिया, 23 सितंबर को थाईलैंड, 25 सितंबर को जापान और 27 सितंबर को सिंगापुर के खिलाफ मुकाबला होगा। इस टूर्नामेंट का स्वर्ण पदक मुकाबला 2 अक्टूबर को खेला जाएगा।

भारतीय महिला टीम के लिए वर्ष 2026 अब तक शानदार रहा है। टीम ने एफआईएच महिला नेशंस कप का खिताब अपने नाम किया और महिला प्रो लीग में प्रमोशन हासिल किया। इसके बाद एफआईएच महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पांचवां स्थान हासिल कर अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया, लगातार बेहतर प्रदर्शन से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है।

अब एशियन गेम्स में भारतीय टीम के सामने स्वर्ण पदक जीतने की चुनौती है। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करना भारतीय टीम के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफिकेशन का रास्ता साफ होगा। ऐसे में सलीमा टेटे की कप्तानी और झारखंड की चार खिलाड़ियों की मौजूदगी पर देशभर की नजर रहेगी।

विधायक के बेटे से मारपीट का मामला, 9 नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज

09

रांची, एजेंसी। चतरा से लोजपा विधायक जनार्दन पासवा न के बेटे सौरभ के साथ रांची में मारपीट और कथित अपहरण मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना 7 सितंबर की शाम नयासराय स्थित अमिटी यूनिवर्सिटी के पास घटित हुई थी। घटना के बाद रांची पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सौरभ को कुछ ही घंटों में सकुशल बरामद कर लिया था।

सौरभ कुमार के द्वारा दर्ज एफआईआर में यह बताया गया है कि वह अमिटी यूनिवर्सिटी रांची में एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। 7 सितंबर 2026 को वह रोज की तरह यूनिवर्सिटी में लॉ की क्लास करने गया था। क्लास खत्म होने के बाद वह अपने साथी अमरदीप और अनमोल रविशंकर के साथ कॉलेज गेट के पास खड़ा था। इसी दौरान एक लड़की ने उसके दोस्त अमरदीप से कुछ बातचीत की। शिकायत के अनुसार, इसके बाद लड़की ने अपने परिचित लड़कों को फोन कर बुलाया। सोमवार को शाम 4।15 बजे के करीब दो काली रंग की गाड़ियों से कई युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि वहां पहुंचे युवकों ने सौरभ कुमार और उसके दोस्तों के साथ लाठी-डंडे से मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर उसके दोस्त अनमोल को थप्पड़ मारा गया। इसके बाद सौरभ को जबरन गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि गाड़ी में सवार लोगों ने सौरभ और उसके साथियों से मोबाइल फोन और करीब 20 ग्राम वजन की सोने की चेन छीन ली। इसके अलावा सौरभ का गला दबाया गया, जिससे उसे सांस लेने में काफी परेशानी हुई। बाद में सौरभ के दोस्तों ने घटना की जानकारी उसके भाई और पुलिस प्रशासन को दी। इसके बाद पुलिस के आने की सूचना मिलने पर आरोपी कथित तौर पर विधानसभा थाना क्षेत्र में सौरभ को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की उसमें लक्की राज, आयुष मिश्रा, प्रकाश कुमार, रौनक सिंह, प्रीतम सिंह, राहुल बनिया, बाबू साहेब आयुष, शौर्य राज और अन्य अज्ञात लोग शामिल है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि रोहित सिंह उर्फ तोता अपनी कार लेकर आया था और उसने भी मारपीट की। सौरभ ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। विधानसभा थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 69/2026 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3), धारा 127(2), धारा 115(2), धारा 351(2), धारा 352 और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नदियों पर कब्जा कर रहे हैं कास, बदल रही है जलधारा, प्राकृतिक और धार्मिक महत्व भी है खास

पलामू, एजेंसी। झारखंड के पलामू जिले में कई नदियां बहती हैं, जिनकी जलधारा धीरे-धीरे बदलती जा रही है। मानवीय गतिविधियां तो इसका एक कारण हैं ही, एक और बड़ा कारण है- कास। यह घास नदी के किनारे पर उगता है और बारिश के बाद खाली गाद तथा बालू पर बहुत तेजी से घने झुरमुट बना लेता है। इसके कारण वहां से बहने वाली जलधारा को मजबूरन अपना रास्ता बदलना पड़ता है।

कास आज पलामू की नदियों की धारा को तेजी से बदल रहा है। पलामू में सोन, उत्तरी कोयल, अमानत, औरंगा, बटाने तथा कनहर जैसी नदियां बहती हैं। इन सभी नदियों में कास ने तेजी से कब्जा जमा लिया है। एक दशक पहले तक कास मुख्य रूप से सोन नदी और दलदली इलाकों तक सीमित था। धीरे-धीरे इसने पलामू से गुजरने वाली लगभग सभी नदियों में अपना विस्तार कर लिया है। इनमें सबसे अधिक प्रभावित उत्तरी कोयल नदी हुई है। उत्तरी कोयल नदी में कास बढ़ने के कारण मेदिनीनगर और चैनपुर के कुछ इलाकों में नदी की धारा बदल गई है। मेदिनीनगर के सिंगरा खुर्द, सिंगरा कला तथा चैनपुर के चेडाबार, पूर्वडीहा और केकतुआ जैसे क्षेत्रों में कास ने धारा को प्रभावित किया है। इन इलाकों में कोयल नदी का पानी खेतों में घुस गया है।

पलामू के हुसैनाबाद इलाके में कास के कारण दियारा (स्थानीय भाषा में डीला) बन गया है। सोन नदी का जलस्तर बढ़ने पर इन क्षेत्रों में चेतावनी भी जारी की जाती है। सोन नदी का डीला चारों तरफ से कास से घिरा हुआ है। हुसैनाबाद के देवरी, दंगवार समेत कई गांवों में मिट्टी का कटाव भी हो रहा है।

चैनपुर के पूर्वडीहा निवासी विकास दुबे बताते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में कोयल नदी में कास नहीं देखा था। अब हर जगह कास दिख रहा है। जिसके कारण नदी अपनी धारा बदल रही है, मिट्टी का कटाव हो रहा है और खेत नदी में समाते जा रहे हैं। वे कहते हैं कि कास को नियंत्रित या नष्ट करने का कोई प्रभावी उपाय निकाला जाना चाहिए, ताकि किसानों और ग्रामीणों को राहत मिल सके। पलामू प्रमंडल में कोयल नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में सबसे अधिक आबादी बसी हुई है। 2026 में उत्तरी कोयल में कई वर्षों बाद बाढ़ आई। बाढ़ का पानी शहरी आबादी वाले इलाकों में घुस गया। कास के घने कब्जे के कारण पानी तेजी से नहीं निकल सका और आबादी वाले क्षेत्रों में फैल गया।

कास जंगली प्रजाति की घास है। यह भारत का मूल निवासी पौधा है। पहले नदियों के दोनों छोर पर कास, पुटुस, जंगली अरहर और अकवन के पौधे एक साथ मिलते थे। धीरे-धीरे पुटुस, जंगली अरहर और अकवन विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में कास को कांस, काश, खासी फूल, राड़ी या रेड़ी के नाम से जाना जाता है। अब कास नदी के किनारे से निकलकर नदी के बीच में भी पहुंच गया है। पहले ये पौधे नदियों के किनारे मिट्टी के कटाव को रोकते थे। अब इनमें से मुख्य रूप से कास ही बच पाया है और यह नदियों की धाराओं को बदल रहा है।

कास के पौधे नदियों के किनारे तथा रेतीली जमीन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इसके फूल बेहद हल्के होते हैं, जो हवा के साथ आसानी से उड़ जाते हैं और नदी के पानी में बहते हुए एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंच जाते हैं।

2014 में झारखंड में बालू घाटों की नीलामी हुई थी। उसके बाद पलामू की कई नदियों में तेजी से बालू का उठाव हुआ। इससे मोटे बालू में मिट्टी का अंश मिल गया। विशेषज्ञों के अनुसार, कास पतले बालू (जिसमें मिट्टी का अंश हो) में ही अच्छी तरह पनपता है। पलामू में कास के तेजी से फैलने का यह एक प्रमुख कारण है।

वन्यजीव विशेषज्ञ एवं शोधकर्ता प्रोफेसर डी।एस। श्रीवास्तव कहते हैं, 'कास को लेकर कई वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं। कास के साथ रहने वाले पुटुस, थेथर, अकवन और जंगली अरहर धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे हैं। ये सभी धाराओं को नियंत्रित करने में मदद करते थे। अब दूसरे पौधे खत्म हो गए हैं और सिर्फ कास बच गया है। कास की खासियत है कि वह मिट्टी के कटाव को रोकता है, लेकिन इसकी सीमा है।

यह पतली मिट्टी को ही पकड़ता है, बड़े बालू कणों को नहीं। इसकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं और यह बेहद कम पानी में भी पनप जाता है। पानी में इसके फल और फूल गिरते हैं, जो दूर तक ले जाए जाते हैं और नदी की धारा में भी उग जाते हैं। दूसरे झाड़ीनुमा पौधों की जगह मिलने तथा बालू उठाव के कारण कास को अधिक स्थान मिल गया है। बालू उठाव इसका एक कारण है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं। कास के फूल को मौसम का इंडिकेटर माना जाता है। मान्यता है कि कास के फूल खिलने के बाद मानसूनी बारिश लगभग समाप्त हो जाती है और मानसून के विदाई का समय आ जाता है। फूल खिलने के बाद मौसम करवट लेता है और ठंड का आगमन शुरू होता है।

संक्षिप्त समाचार

गढ़वा पहुंची भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा, देवेंद्र नाथ महतो ने दी चेतावनी, कहा- न्याय नहीं मिला तो झारखंड में होगा चक्का जाम

गढ़वा, एजेंसी। जेएलकेएम छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अपनी 'भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा' के आखिरी चरण में गढ़वा पहुंचे। रंका मोड़ पहुंचने पर छात्रों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वे उन्हें कंधों पर बिठाकर लगभग आधा किलोमीटर दूर प्रसिद्ध मां गढ़देवी मंदिर ले गए, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद मांगा। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार, गढ़वा पहुंचने पर छात्रों ने देवेंद्र नाथ महतो का भव्य स्वागत किया। महतो अभी झारखंड के सभी 24 जिलों का दौरा कर रहे हैं ताकि भर्ती व्यवस्था में सुधार हो सके। इसी अभियान के तहत वे गढ़वा जिले पहुंचे। यह दौरा सबसे पहले भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचा। इसके बाद, जब वे गढ़वा जिला मुख्यालय पहुंचे, तो रंका मोड़ पर इंतजार कर रहे छात्रों ने उनका स्वागत किया और जोश के साथ नारे लगाए। इस दौरान छात्र उन्हें लगभग आधा किलोमीटर तक अपने कंधों पर उठाकर ले गए। फिर उन्होंने प्रसिद्ध मां गढ़देवी मंदिर के दर्शन किए, जहां उन्होंने श्रद्धापूर्वक नमन किया, पूजा की और आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर बोलते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि झारखंड के छात्रों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि सभी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि वे की कार्रवाई पर कड़ी नजर रख रहे हैं। उनके अनुसार, अभय तिवारी के करीबी लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन कई अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई अभी बाकी है। उन्होंने घोषणा की कि अगर आंदोलन के बावजूद छात्रों को न्याय नहीं मिला, तो पूरे राज्य में 'चक्का जाम' किया जाएगा। भर्ती सुधार यात्रा का यह चरण गढ़वा में संपन्न हुआ। इस दौरे का समापन रांची में होना है। झामुमो पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गढ़वा में जेएमएम के कुछ गुंडे और कार्यकर्ता छात्रों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने गढ़वा की धरती से कड़ी चेतावनी देते हुए जेएमएम सदस्यों से कहा कि वे अपनी हरकतें सुधारें और छात्रों को निशाना बनाना बंद करें। वरना, सिर्फ आंदोलन ही नहीं, बल्कि पूरा झारखंड जलता हुआ दिखाई देगा।

दावा-आपत्ति के सुनवाई स्थल पर होगा टोकन सिस्टम, लोगों की भीड़ को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश

रांची, एजेंसी। दावा-आपत्ति की सुनवाई के दौरान लगने वाले भीड़ और हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने टोकन सिस्टम शुरू करने का निर्देश दिया है। राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के। रवि कुमार ने आज बुधवार यह निर्देश दिया। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण, दावा-आपत्ति एवं सुनवाई, युवा मतदाता पंजीकरण, श्वस्ट गतिविधियों तथा मतदाता सेवाओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कार्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दावा-आपत्ति की सुनवाई के दौरान अनावश्यक भीड़ न लगने दें और एक साथ अधिक लोगों को बुलाने के बजाय टोकन सिस्टम के माध्यम से क्रमवार सुनवाई कराई जाए।उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाए और उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों के परीक्षण के बाद नियमानुसार निर्णय लिया जाए।जिला निर्वाचन पदाधिकारी लंबित मामलों एवं प्रतिदिन हो रहे निष्पादन की नियमित समीक्षा करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि शून्य तथा 1 से 5 फॉर्म-6 वाले मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया जाय और ऐसे मतदान केंद्रों की मतदान केंद्रवार समीक्षा करते हुए बीएलओ के माध्यम से उन नए एवं युवा पात्र भारतीय नागरिकों की पहचान की जाए, जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। ऐसे सभी पात्र नागरिकों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 एवं आवश्यक घोषणा-पत्र प्राप्त कर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे साथ ही साहेबगंज में सामने आई अनियमितता की पुनरावृत्ति किसी अन्य जिले में न हो, इसके लिए आवेदन, दस्तावेज, सत्यापन एवं निर्वाचन डेटा पर प्रभावी निगरानी रखी जाए तथा किसी भी अनियमितता पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाए। के। रवि कुमार ने 19 एवं 20 नवम्बर को राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले श्वस्ट कार्यक्रमों की तैयारियां अभी से प्रारंभ करने का निर्देश दिया। इसके लिए श्वस्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर स्पष्ट जिम्मेदारी निर्धारित करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर विद्यार्थियों एवं युवा मतदाताओं के बीच श्वष्टद्बह्वश्वञ्ज का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा उन्हें उपलब्ध डिजिटल मतदाता सेवाओं की जानकारी दी जाए। उन्होंने ह्लङ्कस्क्कपर प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन तथा श्वष्टद्बह्वश्वञ्ज की 'क्क्रश्चश्च ड्ड ष्टड्डद्यद्य' सुविधा के माध्यम से प्राप्त मतदाताओं की शिकायतों एवं समस्याओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिला स्तर पर इन मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।

धनबाद में जल संकट! पीने के लायक नहीं बचा पानी,

फ्लोराइड और फिनोल सबसे बड़ा खतरा

धनबाद, एजेंसी। देश की कोयला राजधानी धनबाद। जिसके जमीन के नीचे कोयले का अथाह भंडार और ऊपर खनन गतिविधियों से भागती जिंदगी है। लेकिन अब इसी जमीन के नीचे मौजूद पानी को लेकर एक वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आई है, जो चिंता बढ़ाने वाली है।

आईआईटी आईएसएम के पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के एचओडी प्रो। आलोक कुमार सिन्हा के नेतृत्व में हुए शोध ने जिले के अलग-अलग इलाकों से लिए गए 262 पानी के नमूनों की जांच की। 54।96 प्रतिशत नमूने पीने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यानी जिन जलस्रोतों पर लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए निर्भर हैं, उनमें से आधे से ज्यादा पानी वैज्ञानिक जांच के आधार पर सीधे पीने के लिए सुरक्षित नहीं माना जा सकता। बलियापुर के घड़बड़ गांव में पवन सरकार रोज एक ही शिकायत दोहराते हैं। पाइपलाइन महीनों से बंद है। मजबूरी में जो पानी मिलता है, वही पीना पड़ता है। पानी बाल्टी में रखने पर लाल परत जम जाती है। इलाके में लंबे समय से

पानी की समस्या बनी हुई है। पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति महीनों से बंद है। मजबूरी में लोग उपलब्ध पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पानी के सेवन के बाद लोगों को हड्डी और कमर दर्द, दांतों से जुड़ी परेशानी और सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी को बाल्टी में रखने पर लाल रंग की परत जम जाती है। फिल्टर किया हुआ पानी नियमित रूप से नहीं मिल रहा है और कई बार नदी के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। गांव में पानी की टंकी तो बनी हुई है, लेकिन उससे भी नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है।

बलियापुर के ग्रामीण किशन मुखर्जी बताते हैं कि इलाके के बड़ी संख्या में लोग पानी की समस्या से प्रभावित हैं। शारीरिक कमजोरी के कारण लोग खेती-बाड़ी और मेहनत-मजदूरी तक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से साफ पानी की नियमित आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है।

वहीं, बलियापुर प्रभावित क्षेत्र घड़बड़ गांव के स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। पवन सरकार ने बताया कि इलाके में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है। पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति भी महीनों से बंद है। मजबूरी में लोग उपलब्ध पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि पानी के सेवन के बाद लोगों को हड्डी और कमर दर्द, दांतों से जुड़ी परेशानी और सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों के मुताबिक, पानी को बाल्टी में रखने पर लाल रंग की परत जम जाती है। फिल्टर किया हुआ पानी नियमित रूप से नहीं मिल रहा है और कई बार नदी के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। गांव में पानी की टंकी तो बनी हुई है, लेकिन उससे भी नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है। किशन मुखर्जी ने बताया कि इलाके के बड़ी संख्या में लोग पानी की समस्या से प्रभावित हैं। उनका कहना है कि शारीरिक कमजोरी के कारण लोग खेती-बाड़ी और मेहनत-मजदूरी तक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से साफ पानी की नियमित आपूर्ति तथा पानी की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है।

जनवरी 2025 में जिले के अलग-अलग हिस्सों में जल नमूना संग्रह अभियान चलाया गया। डगवेल, हैंडपंप, ट्यूबवेल, तालाब और दूसरे जलस्रोतों से कुल 262 नमूने लिए गए। इन नमूनों में पानी की अम्लीयता, घुले हुए पदार्थ, लवण, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, फिनोल और कई भारी धातुओं की जांच की गई। यह सामान्य पानी की जांच नहीं थी। यह धनबाद के पानी की रासायनिक प्रकृति और उसके पीछे छिपे संभावित कारणों को समझने की विस्तृत वैज्ञानिक कोशिश थी।

शोधकर्ताओं ने पानी की गुणवत्ता को एक समग्र सूचकांक के जरिए परखा। इसे जल गुणवत्ता सूचकांक, यानी ईडब्ल्यूक्यूआई कहा गया। इसमें पानी को पांच श्रेणियों में बांटा गया, बहुत अच्छी गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता, खराब गुणवत्ता, बेहद खराब गुणवत्ता और पीने के लिए अनुपयुक्त। 262 नमूनों की जांच के बाद जो तस्वीर सामने आई, वह चिंता बढ़ाने वाली है।

घर-घर पहुंचा नालसा का जागरूकता अभियान, ग्रामीणों को बताए कानूनी अधिकार

● **अगरडीह में 60 दिवसीय मेगा जागरूकता अभियान का 15वां दिन, लोक अदालत से लेकर साइबर अपराध और बाल विवाह तक दी गई जानकारी।**

किस्को/लोहरदगा। झालसा रांची के आदेश के आलोक में डालसा लोहरदगा के अध्यक्ष राजकमल मिश्रा एवं सचिव मनोरंजन कुमार के निर्देशानुसार गुरूवार को नालसा द्वारा संचालित 60 दिवसीय मेगा जागरूकता अभियान के तहत किस्को प्रखंड क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के 15वें दिन हिसरी पंचायत के अगरडीह गांव में पीएलवी निशा कुमारी, शाहिद हुसैन, कलावती कुमारी, बबलू भगत, कलिंदर

उरांव एवं वीरचंद भगत ने घर-घर जाकर ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इधर अभियान के दौरान ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सहायता, आगामी 12 सितंबर को आयोजित लोक अदालत, मध्यस्थता सहित विभिन्न विधिक सेवाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। वहीं एसिड हमले से पीड़ितों के लिए कानूनी सेवा, मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुंच संबंधी योजना, मानव तस्करी एवं वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित नालसा की योजनाओं के बारे में भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया। पीएलवी शाहिद हुसैन ने ग्रामीणों को नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। किसी भी कानूनी समस्या अथवा आपात स्थिति में संबंधित हेल्पलाइन का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इस दौरान स्पॉन्सरशिप योजना, डायन प्रथा, साइबर क्राइम, बाल विवाह, बाल श्रम एवं सड़क दुर्घटना से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, उपलब्ध विधिक सेवाओं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना तथा जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क कानूनी सहायता की पहुंच सुनिश्चित करना है।

कैरो में मां अम्बे दुर्गा पूजा समिति का पुनर्गठन, शैलेश साहू अध्यक्ष और विवेक प्रजापति बने संयोजक

कैरो (लोहरदगा)। आगामी नवरात्र दुर्गा पूजा को लेकर कैरो के दुर्गावाड़ी भवन में मंगलवार रात मां अम्बे दुर्गा पूजा समिति की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से पूर्व वर्ष की समिति को ही वर्ष 2026 में पूजा आयोजन की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया। शैलेश साहू को अध्यक्ष और विवेक प्रजापति को संयोजक बनाया गया। सुमन सोनी को सचिव, ब्रजेश कुमार को कोषाध्यक्ष तथा अमित साहू, उज्ज्वल कुमार और निशांत पांडेय को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। पूजा प्रभारी के रूप में संजय साहू, विष्णु कुमार और कृष्णा साहू का चयन हुआ। बैठक में पंडाल, रावण निर्माण, प्रसाद वितरण सहित विभिन्न समितियों के लिए भी सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई। आचार्य की जिम्मेदारी कौशल कांत त्रिपाठी को दी गई। समिति के संरक्षक, जनप्रतिनिधि, पहान-पुजार, पुरोहित और क्षेत्र के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

पेंशनरों की समस्याओं को लेकर झारखंड राज्य पेंशनर समाज की बैठक

भरनो (गुमला) : प्रखंड परिसर स्थित पेंशनर भवन में गुरुवार को झारखंड राज्य पेंशनर समाज प्रखंड शाखा भरनो की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष कपिलेश्वर सारंगी ने की। बैठक में पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं,संगठन के संचालन तथा लंबित मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक में कहा गया कि वयोवृद्ध होने के बावजूद पेंशन से संबंधित सरकारी कार्यालयों में पदाधिकारियों की लापरवाही और गलत रवैये के कारण पेंशनरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशनरों ने भी समाज और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।ऐसे में वृद्धावस्था में हमारी समस्याओं का समाधान करना और उनके हितों की रक्षा करना सरकार के साथ-साथ प्रत्येक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है।वहीं बैठक में अन्य सदस्यों ने भी बारी-बारी से पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला।सदस्यों ने कहा कि पेंशन से जुड़े मामलों के निष्पादन में होने वाली अनावश्यक देरी से बुजुर्ग पेंशनरों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने पेंशनरों की समस्याओं के प्रति संबंधित विभागों को संवेदनशील होकर कार्य करने की आवश्यकता जताई।बैठक के दौरान पेंशनर समाज के संगठनात्मक एवं वित्तीय संचालन को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।पेंशनर समाज के संधारण के लिए कैश बुक खरीदने का निर्णय लिया गया।वहीं वार्षिक आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार कर लिए जाने की जानकारी दी गई।इसे आगामी बैठक में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।बैठक में बताया गया कि पेंशनर समाज के बैंक खाते में लंबे समय से लेन-देन नहीं होने के कारण खाता बंद हो गया है।इसे पुनः चालू कराने के लिए केवाईसी अपडेट कराने को लेकर भी चर्चा की गई।बैठक के पश्चात जिला से प्राप्त निर्देश के आलोक में पेंशनर समाज के सदस्यों की न्यायोचित मांगों तथा विलिडेशन एक्ट को निरस्त करने की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी,भरनो के कार्यालय में मांग पत्र सौंपा गया।

पेंशनरों ने अपनी मांगों पर सरकार से सकारात्मक पहल करने की उम्मीद जताई।इस मौके पर कपिलेश्वर सारंगी,फौजदार पांडेय,साहबीआर खान,पुण्यति बड़ा,जगरनाथ महली, नंदन महतो,परमानंद भीमकुल,जगदीश साहू, सुलेमान बड़ा,जयवंती देवी,निमन्ती खलखो,हेमंत कुमार इंदवार, बलदेव महली,मेलो देवी,यशोदा उरांव,विरसपती देवी,अमर नाथ सिंह,दुती देवी सहित बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित थे।

उपायुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक संपन्न स्वास्थ्य सेवाओं में शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश

गुमला: समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आज गुरुवार को उपायुक्त, गुमला दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति, पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन तथा स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक के दौरान मातृत्व स्वास्थ्य के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) एवं संस्थागत प्रसव की प्रखंडवार प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि गर्भवती महिलाओं की नियमित ट्रैकिंग करते हुए छूटे हुए मामलों की पहचान एवं फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए। एएनसी जांच के निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत बनाए रखने तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया गया। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी एवं समय पर आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया।बाल स्वास्थ्य के तहत नियमित टीकाकरण की समीक्षा में जिले की उपलब्धि लगभग 99 प्रतिशत पाई गई। पिछले स्तर की तुलना में लगभग एक प्रतिशत की कमी को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने छूटे हुए सभी बच्चों की पहचान कर उन्हें शत-प्रतिशत नियमित

टीकाकरण से जोड़ने का निर्देश दिया। इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग के साथ मानसी के सहयोग से विशेष प्रयास करने को कहा गया, ताकि कोई भी पात्र बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे।कुपोषण उपचार केंद्र (एमटीसी) की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सरकारी एमटीसी में अधिक से अधिक अति कुपोषित बच्चों को भर्ती कराकर समुचित उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। डुमरी में निजी संस्था द्वारा संचालित एमटीसी केंद्र के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सरकारी एमटीसी की सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा जरूरतमंद बच्चों को सरकारी कुपोषण उपचार केंद्र तक पहुंचाने के लिए प्रभावी स्तर पर जागरूकता एवं परामर्श अभियान चलाने के निर्देश दिए। ममता वाहन की उपलब्धता एवं संचालन की भी समीक्षा की गई।आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं वय वंदना योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले के विभिन्न वार्डों में आयुष्मान मित्रों के माध्यम से विशेष शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जो 15 सितंबर 2026 तक जारी रहेंगे। उपायुक्त ने पात्र लाभुकों का आयुष्मान कार्ड निर्माण सुनिश्चित करने तथा शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। केस क्लेम के लक्ष्य में अपेक्षित सुधार के लिए डुमरी, बिशुनपुर एवं कामडारा में नए आयुष्मान मित्रों को चिह्नित किए जाने की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने वय वंदना योजना में भी पात्र लाभुकों को जोड़ने के लिए अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया।आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आभा कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। वर्तमान में जिले की उपलब्धि 59.21 प्रतिशत है तथा राज्य स्तर पर गुमला जिला छठे स्थान पर है। उपायुक्त ने आभा कार्ड निर्माण की गति बढ़ाते हुए स्वास्थ्य संस्थानों एवं विशेष शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लोगों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने को कहा गया। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से आगामी चार माह की कार्ययोजना के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त ने टीबी के संभावित मरीजों की पहचान, जांच, उपचार एवं नियमित फॉलोअप की प्रक्रिया को प्रभावी बनाए रखने तथा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सतत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सुदिव्य कुमार के निधन से उत्तरी छोटानागपुर में झामुमो की राजनीति में आई शून्यता!

रांची, एजेंसी। पहले झारखंड टाइगर के रूप में चर्चित राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो का असामयिक निधन और अब राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार का दिल के दौरा पड़ने से निधन हो जाने से राज्य ने जहां एक जानकर और तेजतर्रार नेता खो दिया, वहीं यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी एक बड़ी क्षति है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और हेमंत मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे सुदिव्य कुमार सोनू के आकस्मिक निधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उत्तरी छोटानागपुर की राजनीति में शून्यता की स्थिति पैदा हो गई है। अगर मंत्री योगेंद्र प्रसाद और पूर्व मंत्री मथुरा महतो ये दो नाम जरूर उत्तरी छोटानागपुर के झामुमो नेता के रूप में हैं, लेकिन जरूरत के समय पार्टी के लिए हर मोर्चे ओर लड़ने-भिड़ने वाले ग्रासरूट नेता के रूप में सुदिव्य कुमार सोनू की कमी पार्टी को जरूर महसूस होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय झामुमो की राजनीति में आई इस शून्यता को स्वीकार भी करते हैं। वह कहते हैं कि उत्तरी छोटानागपुर में दूर-दूर तक कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता है जो सभी मायनों में सुदिव्य कुमार सोनू की कमी को निकट भविष्य में पूरा कर सके। सुदिव्य कुमार सोनू के असामयिक निधन से आई राजनीतिक शून्यता खास कर उत्तरी छोटानागपुर में कौन भरेगा, इस जगह को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

क्या इस रिक्तता को झामुमो की वरिष्ठ नेता और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भर सकती हैं इस सवाल पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय कहते हैं कि सुदिव्य कुमार सोनू जैसी क्षमता और व्यक्तित्व की भरपाई आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल संकट की इस घड़ी में चारों ओर शून्यता दिखाई दे रही है। पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, उसे सभी कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे। झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य और प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू के जाने के बाद जो वैक्यूम पैदा हुआ है, वह सामान्य राजनीतिक रिक्तता नहीं है। उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली में कई ऐसी खूबियां थीं, जिन्हें पार्टी एक तरह से अपनी 'इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी' मानती थी। किसी भी सवाल का तत्काल और तार्किक जवाब देना, विषय की गहराई को समझना और उस पर निर्णय लेने की क्षमता उनकी खासियत थी।

राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे दिवंगत

सुदिव्य कुमार सोनू की कार्यशैली का जिक्र करते हुए मनोज पांडेय ने कहा कि उनके विभागों में काम करने के तरीके को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों की भी अलग राय थी। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता से जाकर पूछिए, तो बहुत से लोगों का कहना था कि उन्होंने सुदिव्य कुमार सोनू जैसा मंत्री पहले नहीं देखा। उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू हर विषय की बारीकी को समझते थे और निर्णय लेने की क्षमता रखते थे। वह जमीन से जुड़े हुए नेता थे और आम लोगों के साथ उनका सीधा जुड़ाव था। यही वजह थी कि बहुत कम समय में उन्होंने लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता और ख्याति हासिल कर ली। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि समय की पाबंदी और काम करने का अलग तरीका सुदिव्य कुमार सोनू को सबसे अलग करता था। उनकी कार्यशैली में समय की पाबंदी यानी पंक्चुअलिटी भी महत्वपूर्ण थी। वह अपने काम को लेकर गंभीर रहते थे और चीजों को समझकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू की कई खूबियां ऐसी थीं, जिन्हें पार्टी और उनके बाद आने वाले नेतृत्व के लिए सीखने और अनुकरण करने की जरूरत है। उनकी कार्यशैली और विचारों से सीख लेकर ही उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया जा सकता है। उनकी कमी को भर पाना बहुत मुश्किल है।

सुदिव्य कुमार सोनू की जगह किसी दूसरे नेता के आने की संभावना वाले सवाल पर मनोज पांडेय ने कहा कि निश्चित रूप से उनकी कमी को भर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन विधि का विधान है और अब उनकी जगह कोई दूसरा आएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो भी व्यक्ति आगे जिम्मेदारी संभालेगा वह सुदिव्य कुमार सोनू के काम करने के तरीके, उनकी समय की पाबंदी, विषयों की समझ और लोगों से जुड़ने की क्षमता से सीखने और उसका अनुकरण करने का प्रयास करेगा।

सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद उत्तरी छोटानागपुर में उनकी राजनीतिक जगह को लेकर जब कल्पना सोरेन के नाम और उनकी संभावित भूमिका के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस समय संकट की घड़ी है और चारों ओर शून्यता दिखाई दे रही है। ऐसे समय में यह चर्चा करना कि कौन उनकी जगह लेगा और उस रिक्तता को कौन भरेगा, उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की चर्चा और ट्रेंड चलते रहते हैं, लेकिन पार्टी में किसी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय की एक प्रक्रिया होती है। सभी की अपनी-अपनी पार्टी, संगठन और निर्णय लेने का तरीका होता है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने संकेत दिया कि सुदिव्य कुमार सोनू की राजनीतिक विरासत और उत्तरी छोटानागपुर में आगे की भूमिका को लेकर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा। उन्होंने कहा कि झामुमो के नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा, उसे कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि नेतृत्व इतना बड़ा है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय पर किसी एक कार्यकर्ता को भी आपत्ति नहीं होगी।

संक्षिप्त समाचार

बिहार की यह तस्वीर लोकशाही और प्रशासनिक मर्यादा के खुलेआम उल्लंघन को दर्शाती है' : रोहिणी आचार्य

बेगूसराय, एजेंसी। ''सम्राट शासन में सत्ताधारी दल के लोगों को हर नियम-कायदे के उल्लंघन की खुली छूट प्राप्त है। यह तस्वीर लोकशाही और प्रशासनिक मर्यादा के खुलेआम उल्लंघन को दर्शाती है।'' यह कहना है लालू प्रसाद यादव के बेटी रोहिणी आचार्य का। दरअसल, बेगूसराय की एक तस्वीर को लेकर रोहिणी आचार्य ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट किया। कहा सरकारी अधिकारी की कुर्सी पर भाजपा विधायक का बैठना प्रशासनिक प्रोटोकॉल और नियमों का सीधा उल्लंघन है। ये शासन-प्रशासन और सार्वजनिक मर्यादा के मद्देनजर बेहद चिंता का विषय है। दरअसल, बेगूसराय के तेघड़ा से तस्वीर सामने आई। तस्वीर में केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह बैठक की अगुवाई करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ तेघड़ा विधायक रजनीश कुमार और बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता भी बैठे हैं। बैठक में एसडीएम नीरज कुमार सिन्हा, एसडीपीओ कृष्ण कुमार समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। तस्वीर में केंद्रीय मंत्री के साथ दो विधायक एक ही पंक्ति में बैठे नजर आ रहे हैं। जिस कुर्सी पर तेघड़ा विधायक बैठे दिखाई दे रहे हैं, उसे लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या वह एसडीएम की निर्धारित कुर्सी थी 6 सितंबर को तेघड़ा अनुमंडल कार्यालय में बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों से राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली गई और प्रभावित लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए। वैसे तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ाने से लेकर जरूरत पड़ने पर कम्युनिटी किचेन शुरू करने तक की बात हुई। लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, शौचालय की व्यवस्था हो, मेडिकल कैंप लगाए जाएं और किसानों को खाद की किल्लत न हो, इन तमाम मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद चर्चा बाढ़ से ज्यादा एक कुर्सी को लेकर शुरू हो गई।

25 सितंबर से प्रारंभ होगा पितृपक्ष

गया, एजेंसी। बिहार की मोक्ष भूमि गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 25 सितंबर से शुरू हो जाएगा। 25 सितंबर से प्रारंभ होने वाला यह पितृपक्ष मेला 10 अक्टूबर तक चलेगा। मोक्ष भूमि गया जी में वर्ष 2026 का पितृपक्ष मेला 16 दिनों का है। अष्टमी और नवमी की तिथि एक ही दिन है। हालांकि, त्रैपाक्षिक श्राद्ध करने वालों के लिए यह 17 दिनों का होगा। इस वर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी और नवमी का श्राद्ध एक ही तिथि को है। त्रैपाक्षिक श्राद्ध तीन पक्षों के श्राद्ध को कहते हैं। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का त्रैपाक्षिक श्राद्ध 17 दिनों का यानी कि तीन पक्षों का श्राद्ध होगा, जो अनंत चतुर्दशी पूर्णिमा भाद्र शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा से अमावस्या तक आश्विन कृष्ण पक्ष और प्रतिपदा आश्विन शुक्ल पक्ष तक होता है, जो 17 दिनों का होगा। 17 दिवसीय श्राद्ध करने वाले ही त्रैपाक्षिक श्राद्ध करते हैं। हालांकि, ज्यादातर तीर्थयात्री 9 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन और 1 दिन का ही श्राद्ध करने को विष्णुधाम मोक्षभूमि गयाजी को आते हैं और इसके कारण 17 दिनों के लिए आने वाले तीर्थयात्री ही आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की तिथि तक पिंडदान करने को रूकते हैं, जो कि संख्या काफी कम होती है। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की तिथि 11 अक्टूबर की है। ऐसे में त्रैपाक्षिक श्राद्ध करने वालों के लिए पितृपक्ष मेला 17 दिनों का होगा। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 25 सितंबर से शुरू हो जाएगा। हालांकि गया श्राद्ध 26 सितंबर की तिथि से प्रारंभ होगा। आमतौर पर पितृपक्ष मेला 17 दिनों का होता है। किंतु इस बार अष्टमी और नवमी की श्राद्ध तिथि एक ही एक ही दिन पड़ने के कारण यह 16 दिनों का होगा। 25 सितंबर भाद्र शुक्ल पक्ष अनंत चतुर्दशी की तिथि से पितृपक्ष मेला का प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन पुनपुन या गोदावरी श्राद्ध किया जाता है। इस दिन गयापाल तीर्थ पुरोहित का पांव पूजन कर आशीर्वाद लिया जाता है। वही, इसके अगले दिन से गया श्राद्ध की तिथि का प्रारंभ होता है। इस बार गया श्राद्ध की तिथि 26 सितंबर से है।

बिहार में वज्रपात का कहर, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

अररिया, एजेंसी। बिहार में एक तरफ बाढ़ से तबाही मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ वज्रपात ने कहर बरपाया है। अररिया में ठनका गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा तरौना पंचायत के अररबाड़ी गांव के वार्ड संख्या 13 में हुआ। मृतकों की पहचान शिवानंद भगत, वीरेंद्र भगत और कन्हैया भगत के रूप में हुई है। तीनों खेत से मवेशी लाने के लिए गए थे। इसी दौरान अचानक ठनका गिरने से तीनों उसकी चपेट में आ गए और अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजन सुभाष कुमार भगत ने बताया कि शिवानंद भगत उनके चाचा थे, जबकि वीरेंद्र भगत और कन्हैया भगत उनके चचेरे भाई थे। इस तरह एक ही परिवार के तीन लोगों की एक साथ मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सुभाष कुमार भगत ने बताया कि तीनों लोग खेत से मवेशी लाने गए थे। घटनास्थल गांव से करीब छह किलोमीटर दूर है। इसी दौरान ठनका गिरने से तीनों अचेत होकर गिर गए। कुछ देर तक किसी को घटना की जानकारी नहीं मिल सकी। बाद में एक व्यक्ति की नजर तीनों पर पड़ी। उसने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तीनों को उठाकर गांव लेकर आए। इसके बाद शाम के समय परिजन उन्हें वाहन से सदर अस्पताल, अररिया लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मृतकों के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।

सर, हमारा स्कूल चोरी हो गया' कटिहार में शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण

दीघापार गांव में कागज पर बना 44 लाख का स्कूल

कटिहार, एजेंसी। बिहार के कटिहार में स्कूल चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां स्कूल के नाम पर 44 लाख 85 हजार की राशि की निकासी की गई है, लेकिन स्कूल सिर्फ कागजों में है। नाराज ग्रमीणों ने इसकी शिकायत लेकर ढोल-नगाड़े के साथ जिला प्रशासन के पास पहुंचे। प्राणपुर प्रखंड की केहुनियां पंचायत के दीघापार गांव में सरकारी विद्यालय भवन निर्माण के लिए कागजों पर करीब 44.85 लाख रुपये की राशि जारी हो चुकी है। हालांकि, ग्रामीणों का आरोप है कि धरातल पर आज तक भवन की एक ईंट भी नहीं रखी गई। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि संबंधित सरकारी दस्तावेजों में इस निर्माण कार्य के पूर्ण होने का आधिकारिक प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है।

इस अजीबोगरीब भ्रष्टाचार के खिलाफ दीघापार के ग्रामीणों ने एक अनोखे तरीके से जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। स्थानीय ग्रामीण ढोल-नगाड़े बजाते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे और अधिकारियों के समक्ष अपनी गुहार लगाई। ग्रामीणों ने व्यंग्य कसते हुए अधिकारियों से कहा कि 'साहब, हमारा विद्यालय चोरी हो गया है, कृपया आप ही उसे ढूंढकर हमें न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

ग्रामीणों के अनुसार, नए प्राथमिक विद्यालय दीघापार के भवन निर्माण के लिए ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से भूमि उपलब्ध कराई थी। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि वर्ष 2024 में इस भवन निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी की गई थी। बिहार ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदा संख्या 2024_BSEB_314680-1 दर्ज है। इसके बाद 25 मार्च 2025 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी हुआ।

विभाग द्वारा विद्यालय निर्माण की कुल 44।85 लाख

रुपये की राशि तीन अलग-अलग किस्तों में जारी की गई। रिकॉर्ड के मुताबिक, पहली किस्त 18 अप्रैल 2024 को 15 लाख रुपये, दूसरी किस्त 28 सितंबर 2024 को 15 लाख रुपये तथा अंतिम किस्त 12 मार्च 2025 को 14।85 लाख रुपये आवंटित की गई। इस प्रकार कागजों पर शत-प्रतिशत भुगतान पूरा कर लिया गया।

कागजी दावों के विपरीत ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित स्थल पर विद्यालय भवन तो दूर, निर्माण कार्य की शुरुआत का कोई संकेत तक नहीं है। वर्तमान में उस जमीन पर एक ईंट भी दिखाई नहीं देती है। स्थल की स्थिति देखकर यह अंदाजा लगाना भी पूरी तरह असंभव है कि कभी यहां किसी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया था।

इस गंभीर फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने सर्वप्रथम गांव में एक सामूहिक बैठक आयोजित की। इसके उपरांत भारी संख्या में लोग ढोल-नगाड़ों के साथ कटिहार पहुंचे और अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपनी लिखित शिकायत सौंपी। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

स्थानीय निवासी संतोष कुमार ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2005 में ग्रामीणों ने चंदा एकत्र कर करीब 4।50 लाख रुपये से विद्यालय की व्यवस्था की थी। समय के साथ मिट्टी और टाटी से निर्मित वह पुराना भवन पूरी तरह जर्जर हो गया। आज बच्चों को बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है, ऐसे में भवन के नाम पर 44।85 लाख रुपये की निकासी होना एक बेहद गंभीर मामला है।

ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए और धरातल पर वास्तव में नए विद्यालय भवन का निर्माण सुनिश्चित कराया जाए। विद्यालय भवन बनने से मासूम बच्चों की जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने की मजबूरी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि वे केवल अपने बच्चों के भविष्य और अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं।

प्राणपुर प्रखंड के उप प्रमुख मोहम्मद रफीक ने बताया कि गांव में वर्तमान में विद्यालय संचालित है और यहाँ करीब 10 शिक्षक भी कार्यरत हैं। इसके बावजूद, भवन निर्माण के नाम पर निविदा निकालने और इतनी बड़ी राशि का फर्जी भुगतान होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इसी शिकायत को लेकर अधिकारियों से मिले हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कटिहार सदर एसडीओ सूरज कुमार ने ग्रामीणों को जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण शिकायत लेकर पहुंचे थे कि धरातल पर विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ, जबकि सरकारी राशि की निकासी हो चुकी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ शीघ्र ही स्थल पर जाकर मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जमीन पर विद्यालय भवन बना ही नहीं, तो सरकारी रिकॉर्ड में निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र कैसे जारी हुआ इस निर्माण कार्य की निगरानी किस स्तर पर की जा रही थी इसके अलावा, 44।85 लाख रुपये के पूर्ण भुगतान से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थल का भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया गया

हज यात्रा पर जाएंगे 3637 जायरीन, जमा करनी होगी 1.52 लाख की पहली किस्त

पटना, एजेंसी। बिहार से अगले साल 2027 में कुल 3637 लोग हज यात्रा के लिए रवाना होंगे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार यह संख्या 2026 की तुलना में 1111 अधिक है। चयनित हज यात्रियों को कवर नंबर जारी कर दिए गए हैं और रवानगी अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होगी।

बिहार के हज यात्री पटना एयरपोर्ट के साथ गया एयरपोर्ट से भी रवाना होंगे। देशभर में कुल 19 हवाई अड्डों से हज यात्री जाएंगे। इनमें पटना, गया, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कालीकट, कोच्चि, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कन्नूर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, श्रीनगर और विजयवाड़ा शामिल हैं।

चयनित हज यात्रियों को पहली किस्त के रूप में 1,52,300 रुपये जमा करने होंगे। इसमें 300 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज शामिल है। यह राशि यात्रियों को समय पर जमा करनी होगी। हज यात्रा के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं 65 साल से अधिक उम्र के जरीन (बुजुर्ग) यात्रियों के साथ एक अटेंडेंट का होना अनिवार्य होगा। अटेंडेंट का पूरा खर्च संबंधित यात्री को ही वहन करना होगा।

महिलाएं भी हज यात्रा पर जा सकती हैं, लेकिन उनके कवर में कम से कम कुछ लोगों का होना जरूरी है। यह व्यवस्था सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है।

मुस्लिम आबादी के आधार पर केंद्रीय हज कमिटी बिहार के लिए हर साल करीब 12,000 का कोटा तय करती है। लेकिन पिछले कई वर्षों से बिहार का यह कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है। 2016 में सबसे अधिक 6,533 हज यात्री बिहार से गए थे।

इस प्रकार 2027 में भी बिहार से तय कोटा से काफी कम यात्री हज पर जाएंगे। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार केवल 3,637 लोगों को ही यह अवसर मिल सकेगा, जबकि आवंटित कोटा इससे कई गुना अधिक है।

गरजती रहीं लालू यादव की सांसद बेटी, बगल में बैठकर चुपचाप सुनते रहे सम्राट चौधरी के मंत्री

पटना, एजेंसी। लंबे अरसे बाद मीसा भारती और रामकृपाल यादव एक साथ बैठे नजर आए। मौका था दानापुर प्रखंड कार्यालय में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों को लेकर हुई अनुश्रवण समिति की बैठक का। दिलचस्प यह है कि दोनों राजनीतिक रूप से भले ही अलग-अलग खेमों में हों, लेकिन पारिवारिक रिश्ते में रामकृपाल यादव को मीसा भारती का चाचा कहा जाता है।

बैठक में दोनों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री के वितरण, नावों के संचालन और प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने को लेकर चर्चा की। बैठक में काफी नोक झोंक भी हुई। मीसा भारती ने जहां सरकार पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया, वहीं रामकृपाल यादव ने सरकार की ओर से हर संभव प्रयास युद्ध स्तर पर किए जाने की बात कही।

पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में दानापुर के 6 पंचायत, मनेर के 6 पंचायत में हर वर्ष बाढ़ आती है। दानापुर में तो दोनों तरफ से बाढ़ की समस्या होती है। फुलवारी से लेकर पालीगंज, बिक्रम, मसौढ़ी तक अलग ही तबाही है। फुलवारी में एक भी नाव नहीं है, हम वहां

प्राइवेट नाव चलवा रहे हैं। मसौढ़ी में कोई व्यवस्था नहीं है। बिक्रम और पालीगंज के सीओ कहते हैं, मैडम आप मुहैया करवा दीजिए, हमलोग उसका भुगतान कर देंगे। तो फिर आप क्यों सीओ बने हैं ये तो स्थिति है।''-

दरअसल, दानापुर के दियारा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रखंड कार्यालय के सभागार में बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख वंदना राय ने की। इसमें सांसद मीसा भारती, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। दियारा की छह पंचायतों में बाढ़ की स्थिति और राहत-बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। हाल के दिनों में दानापुर और आसपास के दियारा इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल भी उठाए। खासकर पर्याप्त संख्या में सरकारी नाव उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। मीसा भारती ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री के साथ पर्याप्त नावों का संचालन जरूरी है, ताकि पानी से घिरे लोगों तक समय पर मदद पहुंचाई जा सके। बैठक में राहत सामग्री के वितरण और नाव परिचालन की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की मांग की गई।

ग्लोबल टेंडर की जगह बिहार में फिर से छोटे टेंडर, अक्टूबर में जारी हो सकती है निविदा

पटना, एजेंसी। अशोक चौधरी जब ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री थे, तब हजारों करोड़ के ग्लोबल टेंडर की बात कही गई है लेकिन अब सम्राट चौधरी की सरकार ने सभी टेंडर को रद्द कर नए सिरे से टेंडर निकालने का फैसला लिया है। 237 पुल और 1361 सड़कों के लिए फिर से नई निविदा जारी होगी। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि सभी टेंडर को रद्द कर दिया गया है और नए से टेंडर निकाला जाएगा।

विधानसभा चुनाव से पहले एक साथ कई योजनाओं की निविदा निकाली गई और उस समय विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी ग्लोबल टेंडर को लेकर काफी विरोध जताया। हालांकि बाद में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ग्लोबल टेंडर नहीं नेशनल टेंडर निकाला गया है, जिससे जल्दी से जल्दी काम हो सके। सत्ता पक्ष के

कई विधायकों ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे छोटे ठेकेदार बेरोजगार हो जाएंगे।

अपने ही विधायकों के विरोध के बाद सम्राट चौधरी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार के अनुसार सभी टेंडर को रद्द कर दिया गया है। अब नए सिरे से टेंडर निकाला जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि कई योजनाओं का शिलान्यास भी कर दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत ही तामझाम के साथ योजनाओं का शिलान्यास किया था।

'ग्लोबल टेंडर को रद्द करने पर तो कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है। उन सब योजनाओं को पूरा किया जाएगा, जिसका पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया था। सरकार अपने संसाधन के हिसाब से उस पर काम करेगी। बरसात बाद अक्टूबर से वह दिखेगा भी। '- सुनील कुमार, मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग

टेंडर रद्द होने के बाद अब नया टेंडर निकल नहीं रहा है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि सरकार का खजाना खाली है, इसलिए नया निविदा नहीं निकल रहा है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता अजफर शमशी का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है।

पहले हजारों करोड़ के टेंडर को रद्द किया गया और अब टेंडर नहीं निकलने से ठेकेदारों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। खासकर छोटे ठेकेदार परेशान हैं, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा है। पटना जिले में ठेकेदारी करने वाले सत्येंद्र यादव का कहना है कि टेंडर नहीं निकलने से बहुत दिक्कत है। सरकार को जल्द फैसला लेना होगा।

राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि जब ग्रामीण कार्य विभाग ने एक साथ कई योजनाओं का टेंडर निकाला था तो उसको लेकर काफी विरोध हुआ था,

बिहार में डबल मर्डर, देवर-भाभी की चाकू गोदकर हत्या

मोतिहारी, एजेंसी। बिहार के मोतिहारी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। सड़क पर पानी गिराने जैसी मामूली बात खूनी संघर्ष में बदल गई। पताही थाना क्षेत्र की जिहुली पंचायत के जमुनी टोला गांव में पानी गिराने को लेकर दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान धारदार हथियार से हमला किए जाने का आरोप है। घटना में तीन लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल मरीना खातून (35) और जमील अख्तर (36) की मोतिहारी सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं, घायल मोहसीन अख्तर (40) का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। दोनों मृतक आपस में देवर-भाभी बताए जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि जमुनी टोला गांव में संजय सिंह के घर के समीप सड़क पर पानी गिराने को लेकर बुधवार देर शाम को विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि मोहसीन अख्तर सड़क पर पानी गिरा रहे थे। इसी दौरान संजय सिंह ने उन्हें सड़क पर पानी गिराने से मना किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए।

आरोप है कि कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई और इसी दौरान धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में मरीना खातून, जमील अख्तर और मोहसीन अख्तर घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए पताही पीएचसी पहुंचाया गया।प्राथमिक उपचार के बाद मरीना खातून और जमील अख्तर की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर पताही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मॉडल अस्पताल की बदहाली: ऊपर नाला, नीचे फर्श, 38 करोड़ का मॉडल अस्पताल खुद हुआ बीमार

गोपालगंज, एजेंसी। बिहार के गोपालगंज में लगभग 38 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से बना मॉडल सदर अस्पताल आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जिस अस्पताल को जिले भर के लोगों के लिए बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाना था, वह आज खुद बीमार नजर आ रहा है।

कागजों और दावों में तो मरीजों को यहां इलाज देने का दम भरा जा रहा है, लेकिन धरातल पर स्थितियां इसके बिल्कुल उलट और भयावह हैं। अस्पताल की इस लचर और खस्ताहाल व्यवस्था की सबसे बड़ी बानगी ये है कि पूरे परिसर में चारों तरफ गंदगी और बदबूदार सीवरेज का पानी फैला है।

जल निकासी और सीवरेज सिस्टम की समस्या सबसे गंभीर है। अस्पताल परिसर में उचित नाले और जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण शौचालयों और नालियों का बदबूदार पानी परिसर में खुले में ही बहाया जा रहा है। हालत इस कदर बदतर हो चुके हैं कि इमरजेंसी वार्ड के ठीक बगल में गंदा पानी जमा हो रहा है।

खुले में बहते नाली और शौचालय के पानी से उठने वाली भीषण दुर्गंध ने मरीजों, उनके परिजनों, स्वास्थ्यकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों का सांस लेना तक

दूभर कर दिया है। मरीज जो पहले से ही बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, उन्हें इस बदबू और संक्रमण फैलने के खतरे के बीच दिन-रात बिताने को मजबूर होना पड़ रहा है।

सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो अस्पताल लोगों की बीमारियां ठीक करने का भरोसा देता है, वही परिसर अब बीमारियों का नया अड्डा बन चुका है। अस्पताल निर्माण के समय यह योजना बनाई गई थी कि जिस स्थान पर आज जलजमाव और नाले का पानी जमा हो रहा है, वहां इमरजेंसी का एक नया और सुव्यवस्थित गेट बनाया जाएगा।

मौजूदा स्थिति की बात करें तो निर्माण कार्य पूरा हुए और अस्पताल चालू हुए सालभर का समय बीत जाने के बाद भी यह गेट केवल कागजों तक सिमट कर रह गया है। आज वह जगह किसी डंपिंग जोन या फिर गंदे पानी के तालाब जैसी दिखाई देती है। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल का निर्माण कार्य 2025 में पूर्ण होकर स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हुई।

इस 4-मंजिला मॉडल अस्पताल भवन के निर्माण पर लगभग 37 करोड़ की राशि खर्च हुई है। अस्पताल में आधुनिक वार्ड एवं आईसीयू / एनआईसीयू, गंभीर मरीजों और नवजात शिशुओं के इलाज के लिए अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, सर्वसुविधायुक्त सर्जरी रूम, 5 सौ बेड और सभी बेड तक पाइपलाइन द्वारा ऑक्सीजन की पहुंच है।

दावे तो बड़े हैं लेकिन इमरजेंसी वार्ड के बेड पर मॉनिटर का घोर अभाव है। कुछ ही बेड पर मॉनिटर मौजूद हैं। हालांकि डिजिटल जांच लैब व एक्स-रे, पैथोलॉजी, डिजिटल एक्स-रे और अन्य जांच सुविधाएं मौजूद भी हैं। सुव्यवस्थित ओपीडी व आपातकालीन कक्ष में मरीजों के परामर्श के लिए वातानुकूलित वेटिंग एरिया और 24×7 इमरजेंसी सर्विस भी शामिल है।

इसके अलावा कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनका अभाव भी देखने को मिलता है। अगर बात करें कि किन-किन सुविधाओं का अभाव या कमी है तो अस्पताल में कई अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध होने के बावजूद, उन्हें संचालित करने के लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों और विभिन्न विभागों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी बनी हुई है।

इसके अलावा बिजली व बैकअप की समस्या भी गंभीर है। बताया जाता है कि कई मौकों पर पावर कट के दौरान जनरेटर चालू न होने या इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था न रहने से मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज और सर्जरी करने जैसी स्थिति भी सामने आ चुकी है।

वहीं बारिश के दिनों में अस्पताल परिसर में जलभराव और फॉल्स सीलिंग से पानी टपकने जैसी बुनियादी रखरखाव संबंधी समस्याएं तो आए दिन उजागर होती हैं। साथ ही अस्पताल में कुछ उन्नत लैब जांच की सुविधा न होने के कारण मरीजों को बाहर से टेस्ट कराने की भी सलाह दी जाती है।

एक मरीज के परिजन रामचंद्र मांझी ने कहा कि हम दिघवा दुबौली से अपने भाई की पत्नी का इलाज कराने आए हैं। वहीं अस्पताल परिसर में फैली गंदगी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां बहुत गंदगी, जलजमाव और कचरा है। लोग इलाज कराने आते हैं लेकिन यहां तो स्वस्थ आदमी भी अस्वस्थ हो जाएगा। सफाई होना चाहिए नाला का पानी जम गया है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्डिंग भले करोड़ों की है लेकिन बिल्डिंग बनने से ही नहीं होगा।

संक्षिप्त समाचार

सीपी के साथ यूट्यूबर एआई की मदद से बनाई फोटो, शिकायत

कानपुर , एजेंसी। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल के साथ एक यूट्यूबर ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) की मदद से अपने साथ फोटो बना ली। व्हाट्सएप पर डीपी लगा अब वह रौब गांठ रहा है। मामला सीपी तक पहुंचा तो उन्होंने जांच के आदेश दिए। पता चला कि यूट्यूबर कोहना क्षेत्र का है। उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक की गई तो अखिलेश यादव के साथ भी इसी तरह की एडिटेड फोटो सामने आई। मामले में डीसीपी सेंट्रल से जांच कर कार्रवाई को कहा गया है।

हर साल 15 लाख युवा बन रहे इंजीनियर

कानपुर , एजेंसी। देश इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा है। आजादी के समय सिर्फ 38 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जहां से 300 इंजीनियर निकलते थे। अब हर साल 15 लाख इंजीनियर बन रहे हैं। यह बात उप्र वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (यूपीटीटीआई) में प्लेसमेंट सेल और द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया कानपुर की ओर से आयोजित रायल चार्टर डे में मुख्य वक्ता संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रो. मुकेश कुमार सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसके 99.3 फीसदी भाग का विद्युतीकरण हो चुकी है। आठ हजार रेल कोच निर्माण कर भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। मुख्य अतिथि प्रो. गोपाल दीक्षित ने कहा कि विश्व की कुल वैक्सीन का 60 फीसदी निर्माण कर भारत निर्यात करता है। देश में 400 से अधिक स्टार्टअप हैं। प्रो. आलोक कुमार, विवेक अस्थाना, डॉ. प्रदीप कुमार, आरके श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

तकनीक के साथ कौशल बढ़ाते रहें इंजीनियर

लखनऊ , एजेंसी। इंजीनियरिंग केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है। समाज की जरूरतों को समझकर व्यावहारिक समाधान देना भी इंजीनियरों की जिम्मेदारी है। बदलती तकनीक के साथ उन्हें अपना ज्ञान और कौशल लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। ये बातें बुधवार को रिवर बैंक कॉलोनी स्थित इंजीनियर्स भवन में मुख्य वक्ता इं. जीएम पांडेय ने कहीं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र की ओर से आयोजित रॉयल चार्टर डे कार्यक्रम में इंजीनियरिंग के इतिहास और तकनीकी विकास में संस्था की भूमिका पर चर्चा हुई। अध्यक्षता कर रहे प्रो. बीआर सिंह ने तकनीकी ज्ञान, नवाचार और निरंतर सीखने पर जोर दिया। कार्यक्रम संयोजक डॉ. जेबी सिंह, मानद सचिव इं. एनके निषाद समेत कई लोग मौजूद रहे।

महिलाओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर होगा सेमिनार

लखनऊ , एजेंसी। लखनऊ विश्वविद्यालय में महिलाओं के स्वास्थ्य प्रबंधन में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की भूमिका पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा। विवि के योग विभाग, फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, इंडियन योग फेडरेशन, यूपी नेचुरोपैथी एंड योग टीचर्स एंड फिजिशियन एसोसिएशन और चेस्ट केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले सेमिनार के पोस्टर और ब्रोशर का विमोचन कुलपति प्रो. जयप्रकाश सैनी ने बुधवार को किया। फैकल्टी के समन्वयक डॉ. अमरजीत यादव ने बताया कि महिला स्वास्थ्य पर यह 22वां सेमिनार होगा। इसमें पांच वैज्ञानिक सत्र होंगे। विशेषज्ञ महिलाओं से जुड़ी विभिन्न बीमारियों के प्रबंधन में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की भूमिका पर चर्चा करेंगे। योगासनों का वैज्ञानिक प्रदर्शन भी किया जाएगा। क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशेषज्ञों को सम्मानित किया जाएगा। महिलाओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

साइबर ठगी की ऐसी वारदात, जो सोचने पर कर देगी मजबूर; खाता लॉक था फिर भी उड़ गए रुपये!

आगरा, एजेंसी। पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते से 99 80 हजार रुपये साइबर ठगों ने दूसरे खाते में स्थानांतरित कर लिए। पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की। बैंक को सूचना देकर खाते को लॉक करवाया। इसके बाद भी उनके खाते से 14 हजार रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित ने पुलिस आयुक्त को प्रार्थनापत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। सूर्य लोक कॉलोनी, मऊ रोड निवासी लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि इंडियन बैंक की खंदारी शाखा में उनका और पत्नी कांति देवी का संयुक्त खाता है। 1 सितंबर को साइबर अपराधियों ने उनके खाते से 99,800 रुपये निकाल लिए। रकम मुंबई के शिवम छेदीलाल सरोज नाम के बैंक खाते में गई। उन्होंने साइबर हेल्पलाइन, थाना पुलिस दोनों जगह शिकायत की। बैंक शाखा में लिखित शिकायत कर खाते को लॉक कराया। इसके बाद भी 3 सितंबर को उनके खाते से 14 हजार रुपये निकल गए। उनके साथ कुल 1,13,800 रुपये की साइबर ठगी हुई है। बैंक में बताया जा रहा है कि एक संचार कंपनी की एप डाउनलोड कर उनके खाते से यह रकम स्थानांतरित की गई है। मामले में डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

यूं ही नहीं लाल-नीला संगम

बसपा के खिसकते जनाधार पर सपा की नजर

लखनऊ , एजेंसी। समाजवादी पार्टी ने अपनी छात्र विंग की ड्रेस का रंग नीला यूं ही नहीं किया है। राजनीतिक गलियारों में इसे महज संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा की रणनीतिक चाल माना जा रहा है।

आंबेडकरवादी मतदाताओं के बीच नीले रंग के भावनात्मक जुड़ाव को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की नजर इस वर्ग पर है। अखिलेश यादव की रणनीति भी इसी दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है।

इसका मुख्य उद्देश्य सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले में डी यानी दलित वर्ग की भागीदारी को केवल चुनावी नारा न रखकर जमीन पर उतारना है। विरोधी दल सपा पर दलितों को सांकेतिक महत्व देने का आरोप लगाते रहे हैं।

छात्र सभा की ड्रेस में नीले रंग को प्रमुखता देकर पार्टी दलित समाज की पहचान और विचारों से अपने जुड़ाव का संदेश दे रही है। उत्तर प्रदेश में बसपा के कमजोर होने के बाद दलित समुदाय विकल्प की तलाश में है और सपा की सीधी नजर इसी जनाधार पर है। नीले रंग के प्रतीकात्मक इस्तेमाल से सपा दलित मतदाताओं को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी मंच पर उन्हें वही सम्मान मिलेगा, जो बसपा के मंच से जुड़ा रहा है।

विश्वविद्यालय और कॉलेज राजनीति के जरिए युवा दलितों में पैठ बनाना सपा की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। इससे नए युवा कार्यकर्ता तैयार करने के साथ लाल-नीले राजनीतिक और वैचारिक तालमेल की जमीन भी बन सकती है। अखिलेश बार-बार पीडीए को प्रेम, दया और अपनापन बताते रहे हैं। अब देखना होगा कि यह रणनीति चुनावी सफलता में कितनी बदलती है।

अखिलेश यादव ने भाजपा को लोकतंत्र का दुश्मन बताया

बोले... भाजपा फैला रही है नफरत

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने

भाजपा को लोकतंत्र का दुश्मन और बेईमानों का गिरोह बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस-नहस कर नफरत फैला रही है। अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण को धोखा देने का आरोप लगाया।

समाजवादी सरकार के सिग्नेचर बिल्डिंग और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर बेच दिए गए। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी चरम पर है। प्लासियो मॉल, किसान बाजार और कन्नौज का काऊ मिल्क प्लांट सहित कई सरकारी चीजें बेची गईं।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने दस साल में उत्तर प्रदेश के विकास को बर्बाद किया है। हाईवे, एक्सप्रेसवे और जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने भाजपा को किसान, नौजवान, मजदूर विरोधी बताया और महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच रहने को कहा, 2027 में जीत का विश्वास जताया।

अखिलेश से मिले लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह

लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लोहिया ट्रस्ट में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। सुनील सिंह ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत सकारात्मक रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों, युवाओं, मजदूरों और आम जनता के मुद्दे महत्त्वपूर्ण हैं। 2027 में प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों और दलों के बीच संवाद जरूरी है।

पुस्तक का किया विमोचन

अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में डॉ. लोहिया सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्हें विभिन्न पुस्तकें भेंट की गईं और एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ। अयोध्या धाम के महंत रामदासजी महाराज (बालयोगी) ने अखिलेश यादव को सीइंग इक्वली पुस्तक भेंट की। इस पुस्तक को अनंतानंद, राम बचन और सुनीता विश्वनाथ ने संपादित किया है। इतिहासविद राजमोहन गांधी ने इस पुस्तक की प्रशंसा की है। इसके अलावा पीडीए क्रांति का विमोचन किया।

यूजीसी कानून वापसी की मांग, एक बड़ी लड़ाई की हो गई तैयारी; सवर्ण ट्रैक्टर मार्च की हुई घोषणा

आगरा, एजेंसी। यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर कुबेरपुर स्थित एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के नीचे सवर्ण समाज एवं सर्व समाज की ओर से चल रहा आंदोलन मंगलवार को प्रशासन के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया।

बुधवार को आंदोलनकारियों के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी मनीष बंसल से मुलाकात कर सरकार से वार्ता कराने की मांग रखी। छह सितंबर को यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण महापंचायत आयोजित की गई थी। बाद में महापंचायत अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील हो गई। तीन दिन तक धरना जारी रहा। इस दौरान तहसील और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से वार्ता का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बन सकी।

मंगलवार को एसडीएम एत्मादपुर सुमित कुमार सिंह सहायक पुलिस आयुक्त देवेश कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से वार्ता की। प्रशासन की ओर से पहले जिलाधिकारी और उसके बाद सरकार से वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया। इस पर प्रदर्शनकारियों ने सहमति जताते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर धरना स्थगित कर दिया।बुधवार सुबह 11 बजे छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी मनीष बंसल से वार्ता की। प्रतिनिधिमंडल ने यूजीसी कानून वापस लेने के मुद्दे पर सरकार से वार्ता कराने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दी कि यदि सरकार से वार्ता नहीं कराई गई और कानून वापस नहीं हुआ तो 18 सितंबर को 5 हजार ट्रैक्टर और 50 हजार लोगों के साथ जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। वार्ता में सिस्टम सुधार संगठन (किसान) यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर, सिंगर एमएस ठाकुर, रामवीर सिंह जादौन, पवन सिसोदिया, पंडित नागेंद्र उपाध्याय, प्रवीन सिकरवार, टिंकू पुंडीर, दिनेश उपाध्याय और योगेंद्र सिकरवार मौजूद रहे।

हज समिति की जमीन बिक्री में रिपोर्ट दर्ज, चंदा देने वाले बिल्डर से होगी पूछताछ

लखनऊ , एजेंसी। सपा नेता आजम खां की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब उन पर राज्य हज समिति की जमीन बेचने में गड़बड़ी के आरोप में विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है। आजम उस समय राज्य हज समिति के अध्यक्ष थे।

मामले में तत्कालीन सचिवों लईक अहमद व डॉ. एमएए खान, आमिश डेवलपर्स के प्रोपराइटर मो. अयूब और मुस्तकीम अहमद को भी आरोपी बनाया गया है। विजिलेंस जांच में जमीन की बिक्री से समिति को 2.08 करोड़ रुपये के राजस्व के नुकसान की पुष्टि हुई है।

विजिलेंस के लखनऊ सेक्टर में इंस्पेक्टर ध्रुव चंद्र मौर्य की तहरीर पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक राजधानी के ऐशबाग क्षेत्र के कायमखेड़ा (दुगांवा) में खसरा संख्या-117 में हज समिति की करीब 60 हजार वर्गफीट जमीन थी।

विजिलेंस के लखनऊ सेक्टर में दर्ज हुई एफआईआर, 4 अन्य भी आरोपी : विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि जमीन की बिक्री में आजम व अन्य आरोपियों ने निजी फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया और जमीन बिक्री में नियमों को नजर अंदाज किया गया। जांच के बाद

विजिलेंस ने धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर विवेचना इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह को सौंपी है।

शासन ने तीन मई 2024 को मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच में सामने आया कि आमिश डेवलपर्स को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन बेचने में नियमों का पालन नहीं किया गया।

जौहर ट्रस्ट को चंदा देने वाले रामपुर के बिल्डर खालिद से होगी पूछताछ : पूर्व मंत्री आजम खां के करीबी माने जाने वाले बिल्डर एवं ठेकेदार सैयद खालिद से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूछताछ करने जा रहा है। ईडी उनको समन भेजकर राजधानी स्थित जोनल कार्यालय में तलब करेगा। वह जौहर एसोसिएट फर्म से जुड़े बताए जाते हैं और दिल्ली समेत कई शहरों में रिहायशी प्रोजेक्ट के निर्माण का कार्य करते हैं।

इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक बिल्डर भी रडार पर आ चुके हैं। ईडी ने बीते माह जौहर ट्रस्ट के ठिकानों पर छापे मारे थे, जिसमें कई बिल्डरों और ठेकेदारों द्वारा चंदा देने के सुराग हाथ लगे थे। रामपुर और दिल्ली के यह लोग आजम के करीबियों में माने जाते थे। जांच में पता चला कि बजट की रकम का बड़ा हिस्सा ट्रस्ट को बतौर चंदा दिया गया।

60 करोड़ तक पहुंची रकम

ईडी ने जांच में पता लगाया कि दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, सहारनपुर, मेरठ, बरेली के कई ठेकेदारों, कारोबारियों, शैक्षणिक संस्थानों ने जौहर ट्रस्ट को चंदा दिया था। इनमें से कुछ लोगों से ईडी ने दो वर्ष पहले पूछताछ की थी, उन्होंने कबूला था कि चंदे की रकम का चेक देने के बदले उन्हें नगदी दी गई थी। जांच में 60 करोड़ की राशि चंदे में मिलने और कुछ शेल कंपनियों का इस्तेमाल होने के सुराग मिलने पर दोबारा पड़ताल की जा रही है।

तकरोही में 157 बच्चों पर शिक्षक नहीं

वहीं बेसिक स्कूल पुलगामा में 48 पर चार शिक्षक

लखनऊ , एजेंसी। राजधानी के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात में भारी असंतुलन है। कहीं बड़ी संख्या में बच्चों के मुकाबले शिक्षक कम हैं तो कई स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। प्राथमिक स्कूल तकरोही प्रथम में 157 बच्चों पर एक भी शिक्षक नहीं है। वहीं बेसिक स्कूल पुलगामा में 48 बच्चों पर चार शिक्षक तैनात हैं। ऐसे में कई विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

शिक्षकों के समायोजन से इस असंतुलन में सुधार की उम्मीद थी। आधा सत्र बीतने के बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। लखनऊ के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के 1600 से अधिक परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.36 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इनमें करीब 400 विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। कई प्राथमिक विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे हैं, जबकि दर्जनों स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है।शिक्षकों का कहना है कि सत्र का महत्वपूर्ण समय बीत रहा है। यदि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अंतरिम व्यवस्था नहीं की गई तो शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित

होगी। इसका असर निपुण आकलन पर भी पड़ सकता है।

समायोजन से 90 फीसदी स्कूलों में सुधार का दावा

विभाग के अनुसार, शिक्षकों के समायोजन से करीब 80 से 90 फीसदी विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात में सुधार हो सकता है। इसी उद्देश्य से समायोजन नीति तैयार की गई थी। हालांकि, कानूनी पेचीदगियों और आपत्तियों के चलते मामला अदालत पहुंच गया।

ये पड़ रहा प्रभाव

सरप्लस शिक्षकों वाले विद्यालयों से जरूरतमंद और शिक्षकविहीन स्कूलों में तैनाती नहीं हो पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के मलिहाबाद, सरोजनीनगर और मोहनलालगंज के दूर-दराज के विद्यालयों में स्थिति अधिक गंभीर है।

नगर क्षेत्र के 30 जूनियर विद्यालयों में विषय शिक्षक नहीं

नगर क्षेत्र के चारों जोन में 204 सरकारी विद्यालय हैं। इनमें करीब 30 जूनियर विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की कमी है। कक्षा छह से आठ तक के कई स्कूलों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं हैं। करीब 65 प्राथमिक विद्यालयों में एक शिक्षक और एक शिक्षामित्र के सहारे पढ़ाई चल रही है। करीब एक दर्जन विद्यालयों में शिक्षामित्र या कार्यवाहक शिक्षक व्यवस्था संभाल रहे हैं।

- शिक्षकों के समायोजन का मामला कोर्ट में चल रहा है। निर्णय आने के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरप्लस शिक्षकों का समायोजन होने पर करीब 90 फीसदी स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात सुधर जाएगा।
  - विपिन कुमार, बीएसए
- विभाग की सुस्ती और कानूनी उलझनों का खामियाजा गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ये बच्चे सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर हैं।
  -सुधांशु मोहन, जिलाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट

एएमयू ने पेश किए 100 साल पुराने दस्तावेज

अलीगढ़ , एजेंसी। नगला पटवारी इलाके में स्थित करीब 500 करोड़ रुपये की 3.863 हेक्टेयर जमीन के मालिकाना हक के संबंध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नगर निगम के बीच विवाद में बुधवार को एसडीएम कोल न्यायालय में सुनवाई हुई। इसमें एएमयू ने पुराने और पुख्ता दस्तावेज पेश कर दिए हैं।

बुधवार को एएमयू के प्रतिनिधियों ने अदालत के समक्ष अपने मालिकाना हक को साबित करने के लिए ऐतिहासिक और राजस्व अभिलेख रखे। यूनिवर्सिटी का दावा है कि उनके पास इस जमीन के पुख्ता सबूत हैं। एएमयू की तरफ से कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, उनमें सन 1925 के पुराने दस्तावेज, सन 1941 के राजस्व अभिलेख, सन 1992 की खतौनी पेश की गई। इन सभी पुराने कागजातों के आधार पर एएमयू इस पूरी जमीन पर अपना कानूनी हक जता रही है।

नगर निगम ने मांगा समय, 22 को अगली सुनवाई: एएमयू द्वारा अदालत में दस्तावेज पेश किए जाने के बाद अब नगर निगम को इन पर अपना पक्ष और जवाब रखना है। इसके लिए नगर निगम की ओर से न्यायालय से कुछ समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए एसडीएम कोल डॉ. गजेंद्रपाल सिंह ने अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। एसडीएम न्यायालय ने लिखित स्थगन आदेश भी जारी कर दिया है। इससे पहले डीएम अविनाश कुमार ने मौखिक रूप से जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे।

कैंपस और अस्पताल में जलभराव, छात्रों-मरीजों की फजीहत; अलर्ट

वाराणसी, एजेंसी। काशी में बिजली गिरने और बादल गरजने के साथ 40 मिलीमीटर जोरदार बारिश के बावजूद पारा ढाई डिग्री उछल गया। काशी का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया जबकि मंगलवार को 31 डिग्री था। बृहस्पतिवार को भी बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

बुधवार को लंका, बीएचयू, सिगरा, कैंट, चिरईगांव, मंडुआडीह, महमूरगंज, दुर्गाकुंड, चौकाघाट इलाकों में जोरदार बारिश हुई। फातमान रोड बादशाह बाग कॉलोनी में बड़ा पेड़ गिर गया, जिसके नीचे एक्सयूवी दब गई। ढाई घंटे तक रास्ता जाम हो गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भारी बारिश के बाद छात्र और छात्राएं जलभराव से होकर आते-जाते रहे। सैंडल और चप्पल हाथ में लिए छात्राएं क्लास में पहुंची। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में नेत्र रोग विभाग, जांच केंद्र और ओपीडी के पास भारी जलभराव होने से मरीजों की सांसत हो गई। रुद्राक्ष कंवेशन सेंटर के बाहर पानी लगने से सीएम के कार्यक्रम में आए लोग पानी से होकर गुजरते रहे। वहीं कई ऐसे भी इलाके रहे जहां बारिश हुई ही नहीं।

बुधवार को 20 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से हवा बही। यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को काशी में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। दो दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है।

काशी में इस मानसून 50 साल के औसत से 15 फीसदी ज्यादा बारिश हो गई है। काशी में अब तक 794.2 मिली पानी बरस चुका है जबकि औसत बारिश का आंकड़ा 691.8 मिमी तक ही रहा है।

करघे से तकनीक तक, यूपी के हुनर की रंगीन झलक

लखनऊ , एजेंसी। प्रदर्शनी पंडाल में कदम रखते ही उत्तर प्रदेश के हुनर और तकनीक की अलग-अलग तस्वीरें नजर आती हैं। कहीं सेना के इस्तेमाल वाले टेंट का मॉडल है तो कहीं बनारसी साड़ियों की चमकती जरी। एक स्टॉल पर भदोही के कालीनों की बारीक बुनाई लोगों को करीब से डिजाइन देखने के लिए रोक रही है। यूपी टेक्स-2026 के तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगी दो दिवसीय प्रदर्शनी के अंतिम दिन बुधवार को भी लोगों की भीड़ रही। लोग उत्पाद देखने के साथ कारीगरों और उद्यमियों से उनकी खासियत और तैयार होने की प्रक्रिया भी पूछते नजर आए।

भदोही से आए गफ्फार अहमद अपने कालीनों की बुनाई लोगों को समझाते रहे। कोई डिजाइन को करीब से देख रहा था तो कोई इसे तैयार करने में लगने वाले समय के बारे में पूछ रहा था। उन्होंने बताया कि हाथ से बनने वाले कालीन की हर गांठ में कारीगर की मेहनत जुड़ी होती है। इसे तैयार करने में कई दिन लगते हैं।

बनारस से आई सारा के स्टॉल पर महिलाओं की भीड़ रही। कोई साड़ी का पल्लू उठाकर जरी देख रहा था तो कोई रंग और डिजाइन पसंद कर रहा था। सारा लोगों को बनारसी साड़ी की बुनाई और डिजाइन की बारीकियां बताती रहीं। शादी-ब्याह के लिए साड़ी पसंद करने वालों ने खास दिलचस्पी दिखाई।

उन्नाव से आए अरुण के स्टॉल पर सेना के टेंट और ग्राउंडशीट के मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। लोग कपड़े की मजबूती परखने के साथ उसके तैयार होने की प्रक्रिया पूछते रहे। यहां आग और पानी से बचाव वाले फैब्रिक के नमूने भी रखे गए थे। प्रदर्शनी में कहीं पारंपरिक करघे का हुनर दिखा तो कहीं आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल।

कान के बुंदे लिए, लखनवी चिकन सूट को भी सराहा :बेल्जियम निवासी सेवानिवृत्त शिक्षिका बेनटिक भी प्रदर्शनी देखने पहुंचीं। उन्होंने एक स्टॉल से कान के बुंदे खरीदे और लखनऊ की चिकनकारी का सूट भी देखा। उन्होंने इसकी सराहना

बिना प्याज-लहसुन की चाट, लंदन तक स्वाद : लखनऊ के चाट विक्रेता सूर्य प्रकाश तिवारी के स्टॉल पर भी भीड़ रही। उन्होंने बताया कि देशी घी से तैयार चाट में प्याज-लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। गोलगप्पे का पानी हींग और पुदीने से तैयार होता है। शहर में उनकी दो शाखाएं हैं, जबकि लंदन में भी एक दुकान है। उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी इस कारोबार से जुड़ी है। मलाई मक्खन के स्टॉल पर भी ग्राहकों की भीड़ रही। चाट और मलाई मक्खन को एक जिला, एक व्यंजन योजना के तहत प्रदर्शित किया गया।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली को संवारने के लिए अंतरराष्ट्रीय आयोजनों का ही इंतजार क्यों रखरखाव न होने से दोबारा करोड़ों हो रहे खर्च

नई दिल्ली, एजेंसी। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली को एक बार फिर सजाकर तैयार किया गया है। सड़कों को गड्ढामुक्त करने से लेकर फुटपाथ और साइनेज दुरुस्त करने, फव्वारों की सफाई, फूलों के गमले लगाने और लाइटिंग तक की व्यवस्था की गई है। प्रमुख मार्गों से गुजरने पर दिल्ली का बदला हुआ स्वरूप दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि जब बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन के दौरान व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती हैं तो सामान्य दिनों में क्यों नहीं। लोगों के बीच चर्चा है कि काश दिल्ली में बार-बार जी-20 और ब्रिक्स जैसे आयोजन हों, तभी राजधानी इसी तरह सजी-संवरी नजर आए। राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान राजधानी में बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास हुआ था। इसके बाद 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। सड़कों, फुटपाथ और हरित पट्टियों से लेकर फव्वारों, मूर्तियों और रोशनी तक पर बड़े पैमाने पर काम हुआ। लेकिन आयोजन खत्म होने के बाद धीरे-धीरे वही पुरानी स्थिति लौटती गई। जी-20 के दौरान लगाए गए फव्वारों में बाद में काई जम गई थी। ब्रिक्स से पहले इनकी सफाई कराई गई है। वहीं, करीब 6.75 लाख गमलों की व्यवस्था की गई थी। इनमें से बड़ी संख्या में गमले चोरी हो गए या बेहतर रखरखाव नहीं होने के कारण उन्हें विभाग की नर्सरियों में वापस रख दिया गया। समय पर देखरेख नहीं होने से इनमें से कई गमले कबाड़ में बदल गए। सड़कें भी कुछ समय बाद खराब होने लगीं। आयोजन के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों और आयोजन स्थलों से हटाए गए आवारा कुत्ते और बेसहारा पशु भी बाद में फिर उन्हीं इलाकों में दिखाई देने लगे। जी-20 के दौरान करीब 66 प्रमुख सड़कों का कायाकल्प किया गया था। करीब 6.75 लाख गमले लगाए गए, करीब नौ लाख पौधे लगाने की योजना थी, 2200 पेड़ों पर फूलों की सजावट की गई और 125 फव्वारे तथा 70 से अधिक बड़ी मूर्तियां लगाई गई थीं। प्रमुख मार्गों पर करीब 730 लैंप पोस्ट सजाए गए और दीवारों पर म्यूरल बनाए गए।

ओखला में सिलेंडर विस्फोट में पांच घायल, एक की मौत; क्या कहता है सिलिंडर रखरखाव का नियम

नई दिल्ली, एजेंसी। ओखला फेज-1 में सिलिंडर विस्फोट में घायल पांच मरीजों को एम्स के जेपीएन एपेक्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। इनमें चार मरीजों उमेश, अरविंद, मनोज और पंकज का उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय मोहित सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई। मोहित को मूल रूप से गांव गढ़िया जगन्नाथ, विकासखंड अलीगंज, जिला एटा, उत्तर प्रदेश का निवासी बताया गया है। वह अभी 20 दिन पहले टाइफाइड से पीड़ित अपने पिता कर्मवीर सिंह को उपचार के लिए दिल्ली लेकर आए थे। व्यावसायिक आक्सीजन सिलिंडरों के निर्माण, भराव, भंडारण और परिवहन को पीएएसओ (पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी आर्गनाइजेशन) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) के कड़े नियमों के तहत रेगुलेट किया जाता है। इसके लिए गैस सिलिंडर नियम, 2016 लागू होते हैं। भारतीय मानक के अनुसार सिलिंडर की बाडी काली और ऊपरी हिस्सा सफेद होना अनिवार्य है। सिलिंडर पर अंग्रेजी या हिंदी में ''आक्सीजन'' और गैस का प्रकार एवं खतरा संकेतक स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। हालांकि ओखला फेज-एक जिन सिलिंडरों को उतारते समय हादसा हुआ, उनमें इन मानकों का पूरा पालन नहीं हो रहा था। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर पांच वर्ष में एक बार सिलिंडरों की हाइड्रो-स्टेटिक या हाइड्रो-स्ट्रैच टेस्टिंग कराना अनिवार्य है। पास करने के बाद सिलिंडरों के ऊपरी हिस्से पर टेस्टिंग की तारीख और परीक्षण केंद्र का कोड पंच किया जाता है। एक्सपायरी या बिना टेस्ट वाले सिलिंडरों में गैस भरना अवैध है। सिलिंडरों को हमेशा सीधा रखा जाना चाहिए और उन्हें चेन या विशेष सांचों से बांधना अनिवार्य है। यात्रा के दौरान वाल्व को नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षात्मक कैप हमेशा टाइट रखें। कम से कम छह मीटर दूर रखा जाना चाहिए।

जूते में बम का रिमोट छिपाने से लेकर यूरिन जमा करने तक... लाल किला ब्लास्ट की चार्जशीट में खुलासे

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में लाल किले के पास हुए वाहन बम विस्फोट की साजिश में अहम तथ्य सामने आया है। (एनआईए) की ओर से पूर्व में दाखिल आरोपपत्र के अनुसार, विस्फोट करने वाले उमर-उन-नबी ने लाल किले को निशाना बनाने से पहले चांदनी चौक स्थित लाल मंदिर के पास कार खड़ी करने की कोशिश की थी। उमर-उन-नबी ने वहां भारी यातायात और पुलिस की मौजूदगी के कारण वह अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सका और कार मोड़कर लाल किले की ओर चला गया।

सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, उमर 10 नवंबर की शाम 6.37 बजे लाल मंदिर के पास कार पार्क करने की कोशिश करता दिखाई दिया। वहां हालात अनुकूल नहीं मिलने पर उसने यू-टर्न लिया और करीब 13 मिनट बाद शाम 6.50 बजे लाल किले के गेट नंबर चार के पास विस्फोट कर दिया। एनआईए ने इसे दिल्ली में सामने आया पहला वाहन आधारित आईईडी हमला बताया है। आरोपपत्र के अनुसार, उमर ने आईईडी को रिमोट कमांड तंत्र के जरिए विस्फोट किया। यह तंत्र उसके एक जूते में लगाया गया था।

कार के पास मिले जूते की एड़ी से जुड़ा धातु का टुकड़ा फोरेंसिक जांच में टीएटीपी, पोटैशियम और अमोनियम नाइट्रेट की मौजूदगी वाला पाया गया। कार से मिले नमूने के डीएनए का मिलान उमर के माता-पिता से भी हुआ, जिससे उसकी पहचान की पुष्टि हुई। जांच में यह भी सामने आया कि उमर विस्फोटक को सुरक्षित रखने के लिए विशेष सावधानी बरतता था। आरोपपत्र के मुताबिक, वह अपने कमरे को बेहद ठंडा रखता था और वहां से दुर्गंध आती थी। तैयार टीएटीपी को सुरक्षित रखने के लिए उसने पानी भरने वाले बैग भी खरीदे थे। गवाहों के अनुसार, विस्फोटक मिश्रण को स्थिर रखने के लिए उसमें नियमित रूप से पानी डाला जाता था।

पेशाब कमरे में जमा करता रहा: एनआईएऔ के अनुसार, पुलिस की कार्रवाई के बाद फरार उमर ने नूंह में जिस घर में शरण ली थी, वहां भी संदिग्ध व्यवहार किया। मकान मालिक की महिला सदस्य ने बताया कि वह बाहर जाकर पेशाब नहीं करता था, बल्कि उसे पालीथिन में जमा करता था। इससे कमरे में दुर्गंध फैलने लगी थी।

वहीं, जांच एजेंसी को मिले एक दस्तावेज में यूरिया नाइट्रेट आधारित विस्फोटक तैयार करने की विधि का उल्लेख भी मिला, जिसमें यूरिया के स्रोत के तौर पर पेशाब से यूरिया निकालने का विकल्प बताया गया था।

11 लोगों की मौत, 29 घायल: एनआईए के आरोपपत्र के मुताबिक, विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई और 29 लोग घायल हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हाई-इंटेंसिटी ब्लास्ट वेव इफेक्ट बताया गया है। आसपास की संरचनाओं को करीब 17.7 लाख रुपये का नुकसान होने का भी आकलन किया गया है।

दिल्ली-लखनऊ की 3 सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर युवतियां एएसआई के जाल में फंसी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की एक और लखनऊ की दो सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर युवतियों को एक एएसआई ने फॉलोअर बढ़ाने के नाम पर जाल में फंसा लिया। इसके बाद तीनों के साथ घिनौना काम किया। दिल्ली की एक इनफ्लुएंसर ने बिहार के मुजफ्फरपुर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में तैनात एएसआई पर ब्लैकमेलिंग और उसके साथी पर रेप का आरोप लगाया है। एएसआई ने लखनऊ की दो इनफ्लुएंसर को भी अश्लील मैसेज भेजकर उनका शोषण किया। पीड़िता ने यह आरोप लगाते हुए एसएसबी मुख्यालय और नगर थाने में आनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता दिल्ली के आभा नगर एक्सटेंशन में रहती है। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक एएसआई ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल कराने और फॉलोअर बढ़ाने का झांसा दिया। सात दिसंबर 2025 को मुजफ्फरपुर बुलाया।

दिल्ली में 3 दिन के लिए 22 प्वॉइंट पर डायवर्जन और 35 सड़कें बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। इस मौके पर राष्ट्राध्यक्षों और अतिथियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए 35 प्रमुख सड़कों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। आम जनता, यात्रियों, एयरपोर्ट तथा रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए पुलिस ने 22 सड़कों पर डायवर्जन करने के साथ ही वैकल्पिक रास्तों का रूट प्लान तैयार किया है। यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट के विभिन्न टर्मिनलों तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी गई है। सड़क मार्ग से जाने वाले को ट्रैफिक पुलिस ने ये मार्ग सुझाएं हैं। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स सम्मेलन 2026 के मद्देनजर नागरिकों और यात्रियों की सुविधा तथा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आपातकालीन एवं चिकित्सा वाहनः पूरी दिल्ली में आपातकालीन और चिकित्सा वाहनों को 24×7 प्राथमिकता दी जाएगी

और उनका बिना किसी बाधा के आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा। आवश्यक सेवाएं एवं उपयोगिताएंः सभी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और उपयोगिता सेवाओं के संचालन के लिए निर्बाध आवागमन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आईएसबीटी की ओर जाते समय अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें। सार्वजनिक परिवहन एवं मार्गः यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें और निर्धारित वैकल्पिक मार्गों व डायवर्जन प्वॉइंट का पालन करें। वाणिज्यिक यातायातः जिन वाणिज्यिक वाहनों का गंतव्य दिल्ली नहीं है, उनके दिल्ली में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित पार्किंगः अपने वाहन केवल अधिकृत स्थानों पर ही पार्क करें; नियंत्रित मार्गों के 200 मीटर के दायरे में सड़क किनारे पार्किंग सख्त रूप से प्रतिबंधित है।

दिल्ली मतदाता सूची से छह नाम हटाने पर विवाद

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में 31 अगस्त को जारी प्रारूप मतदाता सूची को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने छह मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर स्पष्टीकरण दिया है। बताया गया कि 5 सितंबर को एक सिविल सोसाइटी समूह की ओर से आयोजित जन सुनवाई में आरोप लगाया गया था कि मंगोलपुरी की नीलम, सुनीता देवी, लक्ष्मी देवी, कांता प्रसाद, रेहाना और गुड्डी देवी के नाम गलत तरीके से एएसएसडी (स्थायी रूप से स्थानांतरित/मृत) सूची में शामिल किए गए हैं। सीईओ कार्यालय ने कहा कि नामों से संबंधित कार्रवाई बीएलओ की ओर से 30 जून से 17 अगस्त के बीच घर-घर जाकर की गई स्थानीय जांच के आधार पर की गई है। वहीं, कार्यालय के अनुसार लक्ष्मी देवी, नीलम और सुनीता देवी के स्थायी रूप से स्थानांतरित होने की पुष्टि हुई थी। वहीं रेहाना के मामले में उनके पति मोहम्मद शेर द्वारा गणना फार्म लेने से इनकार करने की बात रिकॉर्ड में दर्ज है। कांता प्रसाद के मामले में परिवार के सदस्य शिवांशु से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें मृत श्रेणी में रखा गया। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट में जिन कामता प्रसाद का उल्लेख है, वह अलग व्यक्ति हैं और उन्होंने अब फार्म-6 भर दिया है। गुड्डी देवी के मामले में मतदाता रिकॉर्ड का विवरण मेल नहीं खाया, जबकि स्थानीय जांच में उनके स्थानांतरित होने की पुष्टि हुई।

सीईओ कार्यालय ने कहा कि किसी पात्र नागरिक का नाम उचित प्रक्रिया और सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं हटाया जाता। आयोग ने पारदर्शी और निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

अमेरिका में भारतीय दंपती की दरियादिली: एआई को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज को दिए 191 करोड़, आंध्र से है कनेक्शन

वाशिंगटन, एजेंसी। भारतीय मूल के एक दंपती ने टेक्सास में अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी अल्मा मेटर को 20 मिलियन डॉलर का दान दिया है। इससे संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड एनालिटिक्स की पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा और 'अमेरिकन ड्रीम' को साकार करने में अप्रवासियों के योगदान को भी रेखांकित किया जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अनुराधा और विकास सिन्हा ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास को 20 मिलियन डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में 191 करोड़ से ज्यादा का दान दिया है। इस तोहफे के सम्मान में, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास 'अनुराधा और विकास सिन्हा कॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस्ड एनालिटिक्स' की स्थापना करेगा। यह कॉलेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट सिस्टम और डेटा एनालिटिक्स पर केंद्रित एक एकेडमिक और रिसर्च हब के तौर पर काम करेगा। यह एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, एडवांस्ड एनालिटिक्स, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी साइंस और लर्निंग टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता को एक साथ लाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में सिन्हा परिवार का निवेश यूनिवर्सिटी के साथ उनके जुड़ाव के साथ-साथ बढ़ता गया है। 2024 में, उन्होंने

'अनुराधा और विकास सिन्हा डिपार्टमेंट ऑफ डेटा साइंस' की स्थापना के लिए तोहफा दिया, साथ ही स्कॉलरशिप, फैकल्टी, रिसर्च और विशेष पहलों को सपोर्ट करने के लिए एंडोमेंट भी दिए। एक साल बाद, उन्होंने एक और बड़ा तोहफा दिया और 'सिन्हा इनोवेशन लैब फॉर डेटा साइंस' की स्थापना की।

दान के बाद मीडिया से बात करते विकास सिन्हा ने कहा, 'शिक्षा ने हमारे जीवन भर हमारे लिए दरवाजे खोले हैं, और हम दूसरों के लिए भी उन दरवाजों को खुला रखना चाहते हैं।' यही एक बड़ी वजह है कि अनु और मुझे इस बात पर इतना पक्का भरोसा है कि यूएनटी छात्रों के लिए क्या कुछ मुमकिन बना सकता है, जिसमें वे छात्र भी शामिल हैं जो शायद किसी दूसरे देश से वही महत्वाकांक्षा और शिक्षा में वही विश्वास लेकर यहां आते हैं, जो कभी हमारे पास हुआ करता था।' हमारे लिए, यह तोहफा उस अवसर को आगे बढ़ाने और यह मानने के बारे में है कि अप्रवासी सिर्फ 'अमेरिकन ड्रीम' में हिस्सा ही नहीं लेते, वे इसे बनाने में मदद भी करते हैं।' उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पीढ़ी की अहम टेक्नोलॉजी में से एक होगी, और इसके भविष्य को आकार देने वाले लोगों को तैयार करने में यूनिवर्सिटी की अहम भूमिका है। यूएनटी के विजन के बारे में जो बात हमें उत्साहित करती है, वह यह है कि यह छात्रों को सिर्फ एआई का इस्तेमाल करना सिखाने से कहीं आगे जाएगा।

रिपब्लिकन जीते तो हर वयस्क को देंगे 5,000 डॉलर, मध्यावधि चुनाव से पहले ट्रंप का बड़ा दांव

डलास, एजेंसी। अमेरिका में नवंबर के मध्यावधि चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अलग-अलग दांव चलने में जुट गए हैं। उन्होंने जनता के सामने एक बड़ा आर्थिक वादा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी नवंबर में प्रतिनिधि सभा और सीनेट में जीत हासिल करती है तो उनकी सरकार अमेरिका के हर वयस्क नागरिक को 5,000 डॉलर का डिविडेंड देगी। उन्होंने यह घोषणा बुधवार को 2026 रिपब्लिकन कन्वेंशन में मुख्य भाषण के दौरान की।

ट्रंप ने 5,000 डॉलर देने की वजह क्या बताई: डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने आर्थिक मोर्चे पर इतनी सफलता हासिल की है कि सरकार लोगों को यह रकम दे सकती है। अपने भाषण में उन्होंने कहा, 'अगर रिपब्लिकन प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में जीतते हैं, तो हमारी जबरदस्त आर्थिक सफलता और ताकत के कारण मैं अमेरिका के हर वयस्क नागरिक को 5,000 डॉलर का डिविडेंड जारी करूंगा।' हालांकि, ट्रंप ने यह नहीं बताया कि इस योजना के लिए इतनी बड़ी रकम का

इंतजाम कैसे होगा। उन्होंने भुगतान की प्रक्रिया या इसे लागू करने के तरीके की भी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।

5,000 डॉलर देने में अमेरिका को कितने पैसे चाहिए होंगे: यही इस घोषणा का सबसे बड़ा सवाल है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में अनुमानित 27 करोड़ वयस्क हैं। अगर हर वयस्क को 5,000 डॉलर दिए जाते हैं तो सरकार को करीब 1.35 ट्रिलियन डॉलर (करीब 1,28,41,339.59 करोड़ रुपये) खर्च करने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने अपने भाषण में इस भारी खर्च का कोई विस्तृत हिसाब या वित्तीय योजना पेश नहीं की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह एलान ऐसे समय आया है जब वह पहले भी आम अमेरिकियों और अलग-अलग वर्गों के लिए सीधे आर्थिक लाभ वाली योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं। जुलाई में शुरू किए गए 'ट्रंप अकाउंट्स' के तहत 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 के बीच जन्म लेने वाले हर अमेरिकी बच्चे के खाते में सरकार की ओर से शुरुआती 1,000 डॉलर जमा किए जाने हैं। माता-पिता भी शुरुआत में हर साल 5,000 डॉलर तक इसमें जमा कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन की ओर से इससे पहले भी ऐसी घोषणाएं हुई हैं। 2025 में ट्रंप ने अमेरिकी सैन्यकर्मियों के लिए 1,776 डॉलर के 'वॉरियर डिविडेंड' का एलान किया था। यह एक बार दिया जाने वाला टैक्स-फ्री बोनस था और करीब 14.5 लाख अमेरिकी सैन्यकर्मियों को इसका भुगतान किया गया। ट्रंप इससे पहले ज्यादातर अमेरिकियों को 2,000 डॉलर के टैरिफ रिबेट चेक देने का प्रस्ताव भी रख चुके हैं। हालांकि, उस प्रस्ताव को लेकर अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने कहा था कि इसे लागू करने के लिए कानून की जरूरत होगी।

फिलीपींस में समंदर के बीच नाव बनी आग का गोला: पांच यात्रियों की मौत और 87 लापता

मनीला, एजेंसी। फिलीपींस में बुधवार को एक यात्री फेरी में अचानक आग लग गई। हादसा देश के पश्चिमी हिस्से में समुद्र में हुआ। आग लगने के बाद बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए। फिलीपींस कोस्ट गार्ड के मुताबिक, हादसे में अब तक कम से कम पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 42 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बचाव अभियान अभी जारी है, इसलिए लापता लोगों की संख्या आगे बदल सकती है।

फिलीपींस कोस्ट गार्ड की प्रवक्ता कमोडोर नोएमी कायाबायब ने बताया कि फेरी पर कुल 134 लोग सवार थे। इनमें 117 यात्री और 17 चालक दल के सदस्य शामिल थे। आग लगने के बाद कई लोगों का पता नहीं चल पाया। अधिकारियों की ओर से फिलहाल 87

लोगों के लापता होने की जानकारी दी गई है, लेकिन बचाव और तलाश का अभियान जारी रहने के कारण यह आंकड़ा बदल सकता है। एमवी जून एस्टर मनीला से रवाना हुई थी। जब फेरी पलावन प्रांत में कोरोन के पास समुद्र में थी, उसी दौरान बुधवार को उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद फेरी पर सवार लोगों के बीच अफरातफरी की स्थिति बनी। हादसे की जगह पश्चिमी फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र में बताई गई है। उपलब्ध जानकारी में आग लगने की वजह के बारे में कोई कारण नहीं बताया गया है। कोस्ट गार्ड के मुताबिक, अब तक 42 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 87 लोग लापता हैं। हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया है कि यह अंतिम आंकड़ा नहीं है। कोस्ट गार्ड की टीमें लगातार बचाव अभियान चला रही हैं और लोगों की तलाश की जा रही है। घटनास्थल की तस्वीरों में कोस्ट गार्ड के जवान बचे हुए लोगों को लाइफ जैकेट फेंकते हुए दिखाई दिए, जबकि पीछे फेरी जल रही थी। छोटी नावों के जरिए भी बचे हुए लोगों को कम गहरे पानी तक लाया गया।

फिलीपींस के द्वीपसमूह में फेरी परिवहन का एक आम जरिया है। तूफ़ान, खराब रखरखाव वाली नावें, क्षमता से ज़्यादा लोगों का सवार होना और सुरक्षा नियमों का ठीक से पालन न होना (खासकर दूर-दराज के प्रांतों में) जैसी वजहों से समुद्री दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

फिलहाल शामिल होने का फैसला टाल सकता है बांग्लादेश, रणनीतिक शर्तों पर अटकी बात

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश ने सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के मक्का रक्षा गठबंधन में शामिल होने का दरवाजा खुला रखा है। हालांकि सैन्य शर्तों और जिम्मेदारियों का पूरा खाका सामने आने तक वह अंतिम फैसला टालने के मूड में दिखाई दे रहा है। इसके तहत किसी एक सदस्य पर हमला बाकी सदस्यों के खिलाफ भी हमला माना जाएगा। बांग्लादेशी रणनीतिक हलकों में सवाल है कि किसी सदस्य पर हमले की स्थिति में ढाका की सैन्य प्रतिबद्धता किस सीमा तक होगी। रिटायर्ड मेजर जनरल फजले इलाही अकबर ने अखबार प्रोथोम आलो में कहा कि सदस्यता पर फैसला लेने से पहले समझौते की हर शर्त और धारा की गहन जांच होनी चाहिए। साथ ही संसद, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों से व्यापक मशविरा होना चाहिए। विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद ने कहा कि ढाका स्थिति का आकलन कर रहा है और किसी भी फैसले में राष्ट्रीय हित प्राथमिकता होगी। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पहले कोई जोखिम न दिखने की बात कही थी। विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संसद में कह चुके हैं कि अगर मौजूदा सदस्य बांग्लादेश को शामिल करना चाहें तो ढाका प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करेगा। जहां एक तरफ इसके समर्थक इसे सैन्य क्षमता मजबूत करने का अवसर मानते हैं। वहीं पूर्व राजनयिक एम. हुमायूं कबीर ने चेताया है कि इस गठबंधन में शामिल होना बांग्लादेश की पांच दशक पुरानी संतुलित और गैर-गुटीय विदेश नीति में बदलाव होगा। सबसे संवेदनशील पहलू पाकिस्तान है। सदस्यता लेना सीधे द्विपक्षीय सैन्य गठबंधन में शामिल होना नहीं होगा, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के बीच सहयोग बढ़ सकता है।

संपादकीय

'जेन-जी' ने बदल दिया चुनावी सिलेबस

अंतिम परिणति तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन 'जेन-जी' के जंतर-मंतर प्रयोग ने चुनावी सिलेबस बदल दिया है. इसका दबाव राजनीतिक दलों-नेताओं पर दिख रहा है. नौकरी देने के अधूरे वायदों के अलावा याद नहीं पड़ता कि देश में कभी शिक्षा, परीक्षा और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों को शासकीय तो दूर, चुनावी एजेंडे में भी प्राथमिकता मिली हो. युवाओं की बढ़ती आबादी के मद्देनजर 'युवा भारत' के नारे सुने जाते रहे हैं, लेकिन उन्हें बेहतर शिक्षा और उपयुक्त रोजगार देकर देश के विकास की मुख्यधारा का इंजन बनाने की योजना सामने नहीं आई. हां, देश और प्रदेशों में अंतहीन पेपर लीक और भर्ती घोटालों की तलवार अक्सर युवाओं के भविष्य पर लटकी नजर आई. कटु सत्य यह भी कि देश का भविष्य कहे जानेवाले युवाओं के भविष्य से इस खिलवाड़ पर छात्रों-युवाओं के नाम पर बने राजनीतिक दलों के संगठन भी मूकदर्शक बने रहे. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का ऑनलाइन जन्म सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की एक टिप्पणी के चलते हुआ, लेकिन जंतर-मंतर पर और उसके बाद उसे मिल रहा समर्थन छात्रों और युवाओं के मुद्दों की अनवरत अनदेखी का परिणाम भी है. बेशक जंतर-मंतर पर और उसके बाद भी सीजेपी से कुछ राजनीतिक दलों-नेताओं का मेलजोल नजर आ रहा है, लेकिन इस सच से मुंह नहीं चुराया जा सकता कि देश के सभी दलों के शासनवाले राज्यों में पेपर लीक और भर्ती घोटाले होते रहे हैं. इसीलिए अब छात्र और युवा, जाति-धर्म-क्षेत्र-राजनीतिक रुझान की सीमाएं लांघ कर शिक्षा, परीक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर कमोबेश सभी राज्यों में सड़क पर उतर रहे हैं. जंतर-मंतर के

बाद झारखंड में भी छात्रों-युवाओं का सफल आंदोलन और उसका राजनीतिकरण दिखा,

तो अब स्कूली शिक्षा की बदहाली के विरुद्ध राज्य-दर-राज्य 'जेन-अल्फा' के भी सड़क पर उतरने की खबरें हैं. जिन छात्र-छात्राओं को स्कूल-कॉलेज की कक्षाओं में होना चाहिए, उनका सड़क पर उतरना देश-समाज की सकारात्मक तस्वीर पेश नहीं करता, पर उन्हें व्यवस्था ने ही मजबूर किया है. बिना भवन और पर्याप्त शिक्षकों के स्कूल चलने की शिकायतें देशभर में आम हैं, पर उनका निराकरण करने के बजाय बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. व्यवस्था की दृष्टि से यह प्रतिबंध उचित लग सकता है, पर स्कूल की खामियां देखने-दिखाने की अनुमति भला कौन-सा प्रशासन देगा? कुछ राज्यों से स्कूली बच्चों के पैदल जिला मुख्यालय पहुंच कर स्कूल की बदइंतजामी प्रशासन को बताने की खबरें भी यही बताती हैं कि निगरानी जिनकी जिम्मेदारी है, वे अपना काम नहीं कर रहे. हमारे यहां निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की त्रिस्तरीय व्यवस्था है. इसलिए शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकते. स्कूल शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद हैं. बुनियाद ही बदहाल है तो उस पर बननेवाली इमारत के हाल की कल्पना ही की जा सकती है. कुछ छात्र मेहनत और किस्मत से प्रतियोगी परीक्षाओं की दहलीज तक पहुंच जाते हैं तो पेपर लीक और भर्ती घोटाले सपने चकनाचूर करने का चक्रव्यूह रचे तैयार मिलते हैं. पेपर लीक के लिए अक्सर कोचिंग माफिया पर उंगली उठती है. बेशक कोचिंग का दिन दूना-रात चौगुना फैलता कारोबार पाक-साफ नहीं है, पर उसके लिए निगरानी तंत्र बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? राजनीतिक-पुलिस-प्रशासनिक संरक्षण बिना ही कोचिंग माफिया इतना ताकतवर हो गया? शिक्षा-परीक्षा तंत्र के राजनीतिकरण से कौन-सा दल और सरकार इनकार कर सकती है? तमाम राजनेता शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, तो कारोबारियों को भी शिक्षा क्षेत्र का मोटा मुनाफा आकर्षित कर रहा है. राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार से ग्रस्त शिक्षा-परीक्षा तंत्र से पारदर्शिता की अपेक्षा ही बेमानी है. राज्य-दर-राज्य अदालत में चुनौती दी गई या रद्द कर दी गई भर्तियों की फेहरिस्त बहुत लंबी बन सकती है, पर वह नौबत तो तभी आती है, जब प्रक्रिया दोषपूर्ण रहे. आखिर दो दशक पहले भी प्रतियोगी परीक्षाएं और भर्ती होती थीं. बेशक तब भी नकल और पेपर लीक के मामले आते थे. भर्तियों में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते थे, पर अपवादस्वरूप, लेकिन अब तो यह परंपरा-सी बन गई है.

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026: लखनऊ ने मारा मैदान, 21वें स्थान पर खिसकी दिल्ली

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 का परिणाम एक ओर कुछ शहरों के लिए राहत भरा है, तो दूसरी ओर इसने कई शहरों की चिंता बढ़ा दी है। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश के लखनऊ का पहला स्थान निश्चित ही उत्साह जगाता है, मगर इसी सूची में दिल्ली का 21वें पायदान पर होना और शीर्ष दस में हिमाचल प्रदेश के सिर्फ एक शहर का शामिल होना कई सवाल खड़े करता है। पहाड़ों को हम स्वच्छ हवा, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता का पर्याय मानते रहे हैं और यदि वहां भी प्रदूषण की दस्तक तेज हो रही है, तो समस्या विकास को लेकर हमारे दृष्टिकोण की भी है। हालांकि, वायु गुणवत्ता में सुधार के मामले में चंडीगढ़ का उदाहरण महत्त्वपूर्ण है। वर्ष 2024 में वह 27वें स्थान पर था, 2025 में आठवें पायदान पर पहुंचा और अब सातवें स्थान पर है। जिन शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, उसके पीछे कई कारण हैं। हरित क्षेत्र बढ़ाने, निर्माण

स्थलों की धूल नियंत्रित करने, कचरे के वैज्ञानिक निपटान, इलेक्ट्रिक वाहनों और यातायात प्रबंधन जैसे उपायों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन-सा शहर सूची में ऊपर है, बल्कि यह भी महत्त्वपूर्ण है कि किस शहर ने सुधार की राह पर चलकर अपने नागरिकों के लिए हवा को स्वच्छ बनाया और कौन केवल कागजी आंकड़ों में ही उलझा रहा। पहाड़ी प्रदेशों में वायु प्रदूषण का बढ़ाना भी गंभीर चिंता पैदा करता है। हैरत की बात है कि हिमाचल का इकलौता शहर कांगड़ा का डमटाल ही स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की सूची में शीर्ष दस में जगह बना पाया है। यह इस बात का संकेत है कि अगर समय रहते नहीं चेते, तो पर्यटन, निर्माण, यातायात और कचरे का दबाव पहाड़ों की हवा को सांस लेने योग्य नहीं छोड़ेगा! सवाल यह भी है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकारें, नगर निकाय, प्रदूषण नियंत्रण संस्थाएं, उद्योग, वाहन या फिर आम नागरिक। इसमें दोराय नहीं कि प्रदूषण को कम करने में सभी की भागीदारी जरूरी है, लेकिन नीति निर्माताओं और कानून प्रवर्तन एजंसियों की जिम्मेदारी अधिक है। स्वच्छ हवा सभी नागरिकों का अधिकार है और इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है।

आज का कार्टून

पूर्वोत्तर की मासूम पुकार और हमारे पूर्वाग्रहों का कड़वा सच

'हमको चीनी मत बोलो, इंडियन बोलो'...

> अरुणाचल प्रदेश, जिसे 'उगते सूरज की भूमि' कहा जाता है, भारत का वह सीमांत प्रहरी है, जो देश की सीमाओं की रक्षा में दिन-रात अडिग खड़ा रहता है। यहां के लोग प्रतिकूल परिस्थितियों, कठोर मौसम और पड़ोसी देशों की विस्तारवादी गिद्ध-दृष्टि के बावजूद पूरे गर्व से सीना तानकर भारतीय होने का जयघोष करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र देश की सुरक्षा व्यवस्था का सबसे संवेदनशील और महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। असम का बिहू, नगालैंड का हार्नबिल, मणिपुर की रासलीला, मिजोरम का चेराव और अरुणाचल के जीवंत जनजातीय उत्सव भारत की सांस्कृतिक पूंजी को अद्वितीय बनाते हैं। पूर्वोत्तर के लोग जब सीमा पर भारतीय सेना के साथ मिलकर 'जय हिंद' का नारा लगाते हैं, तो उनकी देशभक्ति पर संदेह करना या उन्हें सिर्फ उनके चेहरे के आधार पर 'पराया' समझ लेना राष्ट्र के प्रति एक नैतिक अपराध के समान है।

गिरीश पंकज

पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश की घाटियों से गूंजी एक नन्ही बच्ची कार्गा टिंकल गोंगो की तोतली आवाज ने पूरे देश के अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया था। अपने मासूम चेहरे, खिलखिलाती मुस्कान और तुतलाती जुबान में उसने हाथ जोड़कर पूरे अधिकार से राष्ट्रगान गाया और फिर सहज भाव से यह गुहार लगाई कि 'हमको चीनी मत बोलो, इंडिया बोलो'।

उसकी अनुगूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि छह सितंबर की रात दिल्ली में मणिपुर के प्रख्यात गिटारवादक चोंगथाम विक्रम सिंह की हत्या ने एक बार फिर पूर्वोत्तर के लोगों को दुख पहुंचाया। इस घटना के विरोध में मणिपुर की युवा पीढ़ी में गहरा आक्रोश है।

समय-समय पर पूर्वोत्तर के लोगों को लेकर उत्तर भारत के कुछ अल्पज्ञ लोगों की मानसिकता विचलित करती है। जबकि पूर्वोत्तर के लोग न केवल इस देश से, बल्कि यहां की भाषा से भी प्यार करते हैं। मणिपुरी साहित्य का हिंदी में अनुवाद करने वाले कम नहीं हैं। इसी वर्ष जनवरी माह में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली द्वारा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में वहां के लेखकों के साथ एक नवलेखन कार्यशाला आयोजित हुई थी।

वहां अरुणाचल का लगभग हर व्यक्ति भलीभांति हिंदी बोल रहा था, समझ रहा था। मणिपुर में भी हिंदी प्रेमियों की कमी नहीं। वहां विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्ययन हो रहा है। वहां के लोग विशुद्ध रूप से अपने आप को हिंदुस्तान से ही जुड़ा महसूस करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर भारत के कुछ लोग नादानीवश वहां के लोगों के रंगरूप को देखकर कुछ और दुराग्रह पाल लेते हैं।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी नींव विविधता के सम्मान पर टिकी है। यहां भाषा, खान-पान, वेशभूषा और शारीरिक बनावट हर कुछ सौ किलोमीटर पर बदल जाती है। इसके बावजूद, यह अफसोस की बात है कि जब उत्तर-पूर्व का कोई नागरिक देश के अन्य राज्यों, विशेषकर दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु या कोलकाता जैसे महानगरों में कदम रखता है, तो उसे अक्सर तिरछी और अजनबी नजरों का सामना करना पड़ता है।

चेहरे की बनावट, विशेषकर 'मंगोली' नैन-नक्श के कारण उन पर कुछ अपमानजनक टिप्पणियां करना एक आम विकृति बन चुकी है। किराए पर मकान ढूंढ़ने से लेकर शैक्षणिक संस्थानों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवहन तक, पूर्वोत्तर के युवाओं को लगातार यह अहसास कराया जाता है कि वे 'यहां के नहीं हैं'! जब उन्हें विदेशी कहकर पुकारा जाता है, तो उनके भीतर एक गहरी मनोवैज्ञानिक टूटन पैदा होती है।

अरुणाचल प्रदेश, जिसे 'उगते सूरज की भूमि' कहा जाता है, भारत का वह सीमांत प्रहरी है, जो देश की सीमाओं की रक्षा में दिन-रात अडिग खड़ा रहता है। यहां के लोग प्रतिकूल परिस्थितियों, कठोर मौसम और पड़ोसी देशों की विस्तारवादी गिद्ध-दृष्टि के बावजूद पूरे गर्व से सीना तानकर भारतीय होने का जयघोष करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र देश की सुरक्षा व्यवस्था का सबसे संवेदनशील और महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

असम का बिहू, नगालैंड का हार्नबिल, मणिपुर की रासलीला, मिजोरम का चेराव और अरुणाचल के जीवंत जनजातीय उत्सव भारत की सांस्कृतिक पूंजी को अद्वितीय बनाते हैं। पूर्वोत्तर के लोग जब सीमा पर भारतीय सेना के साथ मिलकर 'जय हिंद' का नारा लगाते हैं, तो उनकी देशभक्ति पर संदेह करना या उन्हें सिर्फ उनके चेहरे के आधार पर 'पराया' समझ लेना राष्ट्र के प्रति एक नैतिक अपराध के समान है।

पूर्वोत्तर के प्रति मुख्यधारा के समाज में व्याप्त इस भेदभाव की जड़ें नफरत से ज्यादा गहरी अज्ञानता में हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली और सामाजिक विमर्श में पूर्वोत्तर को कभी वह स्थान मिला ही नहीं, जिसका वह हकदार था। दशकों तक हमारे स्कूली इतिहास और भूगोल की किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गंगा-यमुना के मैदानों तक का विवरण तो विस्तार से पढ़ाया गया, लेकिन अहोम साम्राज्य, लचित बोरफुकन का पराक्रम, रानी गाइदिनल्यू का संघर्ष, ब्रिटिश सेना को रोकने वाले तिरोत सिंग और माटीमुर्ती कनकलता बरुआ के बलिदानों को एक-दो पन्नों में समेट दिया गया।

दिल्ली या मध्य भारत में बैठे औसत नागरिक को यह तक ठीक से ज्ञात नहीं होता कि पूर्वोत्तर के आठ राज्यों, जिन्हें 'अष्टलक्ष्मी' भी कहा जाता है, उनकी राजधानियां, भाषाएं और जनजातीय परंपराएं क्या हैं। जब तक देश का समाज यह नहीं समझेगा कि भारत सिर्फ आर्य और द्रविड़ बनावट तक सीमित नहीं है, बल्कि 'मंगोलायड' और 'आस्ट्रो-एशियाटिक' नस्लें भी इस मिट्टी की उतनी ही सच्ची संतानें हैं, तब तक कार्गा टिंकल जैसी बच्चियों को अपने भारतीय होने का प्रमाण देना पड़ेगा।

वर्ष 2014 में दिल्ली के लाजपत नगर में अरुणाचल प्रदेश के 19 वर्षीय छात्र निडो तानिया की उसके बालों और नैन-नक्श पर फब्तियां कसने के बाद पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। कोविड-19 महामारी के दौरान पूर्वोत्तर के नागरिकों के साथ हुए दुर्व्यवहार, उन्हें किराए के घरों से निकाले जाने और उन पर छींटाकशी किए जाने की घटनाएं यह साबित करती हैं कि हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी गंभीर पूर्वाग्रहों का बंधक है।

राष्ट्र की अवधारणा किसी चेहरे की लंबाई, आंखों के आकार या त्वचा के रंग से तय नहीं होती। राष्ट्र का निर्माण उन साझा मूल्यों, संविधान और भावनात्मक जुड़ाव से होता है, जो नागरिकों को एक सूत्र में पिरोते हैं। विडंबना देखिए कि जब ओलंपिक या अंतरराष्ट्रीय खेलों में मैरी काम, मीराबाई चानू या लवलीना बोरगोहेन देश के लिए पदक जीतकर तिरंगा लहराती हैं, तब सभी भारतीय गर्व से सीना फुलाते हैं, लेकिन जैसे ही वे मंच से नीचे उतरती हैं, उसी क्षेत्र के एक आम छात्र को दिल्ली या बंगलुरु की सड़कों पर अपनी पहचान के लिए जूझना पड़ता है।

यह अब जरूरी हो गया है कि प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक की पाठ्यपुस्तकों में पूर्वोत्तर के इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों, लोककथाओं और भूगोल को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' जैसी पहलों को केवल सरकारी आयोजनों तक सीमित न रखकर स्कूलों, विश्वविद्यालयों और युवा मंडलों के बीच नियमित विनिमय कार्यक्रमों के रूप में जमीनी स्तर पर लागू किया जाए।

भारतीय सिनेमा और धारावाहिकों में पूर्वोत्तर के कलाकारों को रूढ़िवादी किरदारों से बाहर निकालकर मुख्यधारा की भूमिकाओं में समान अवसर दिया जाए। कार्गा टिंकल गोंगो की तोतली जुबान ने देश को जो संदेश दिया है, वह एक चेतावनी भी है और एक विनम्र आह्वान भी। अब समय आ गया है कि हम अपनी संकीर्ण दृष्टि को त्यागें। कार्गा टिंकल की मासूम पुकार का वास्तविक सम्मान तभी होगा, जब किसी भी भारतीय को यह साबित न करना पड़े कि वह विदेशी नहीं, बल्कि इस भारत भूमि का सच्चा सपूत है। मणिपुर के जाने-माने गिटारवादक विक्रम सिंह इसी देश के नागरिक थे।

उनके साथ दिल्ली में जो हुआ, वह एक तरह से अलगाव को बढ़ावा देता है। एक व्यक्ति या उसका समाज अगर किसी भी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह या दुराग्रह रखता है, तो इसका नुकसान केवल उसे नहीं, बल्कि उसके समाज और देश को भी उठाना पड़ता है।

बाहरी उपलब्धियों के मोह से निकलकर आंतरिक शांति की ओर

> तुलना मानव जीवन की सबसे सहज, लेकिन सबसे घातक प्रवृत्तियों में से एक है। संसार में जन्म लेने के साथ ही हम तुलना के समांतर जगत में भी प्रवेश कर जाते हैं। जीवन के लगभग हर पड़ाव पर हमारे हाथ में एक अदृश्य मापनी थमा दी जाती है- 'तुलना की मापनी'। धीरे-धीरे हम स्वयं को अपने भीतर से नहीं, बल्कि दूसरों के संदर्भ में देखना सीख जाते हैं। यही वह क्षण है, जब हमारा आत्ममूल्य अंतस की मापनी को छोड़कर बाहरी पैमानों का मोहताज होने लगता है। स्वस्थ तुलना बुरी नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब यही तुलना प्रेरणा की जगह हीनता, ईर्ष्या, असंतोष और आत्मग्लानि को जन्म देने लगती है। ऐसी दशा में तुलना व्यक्ति को ऊपर उठाने के बजाय भीतर से खोखला करने लगती है।

शिशिर शुक्ला

हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की यात्रा अलग है। दो व्यक्तियों के सामने दिखाई देने वाले परिणाम समान हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे की परिस्थितियां कभी समान नहीं होतीं। सत्य यह है कि हम केवल किसी के जीवन के दृश्य भाग से ही परिचित हो पाते हैं, उसका अदृश्य संघर्ष हम नहीं देख सकते। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को अपनी असफलताओं की मापनी बना लेना एक बड़ी और हानिकारक मानसिक भूल है।

किसी के जीवन की द्युतिमान तस्वीर के पीछे छिपी बेचैनी, संघर्ष, ऋण, असफलताएं, पारिवारिक तनाव या अकेलापन दिखाई नहीं देता। परिणाम यह होता है कि हम अपने वास्तविक जीवन की तुलना दूसरों के जीवन के उस पहलू से करने लगते हैं, जो हमें दिख रहा होता है। यह तुलना स्वाभाविक रूप से हमें असंतोष की ओर ले जाती है।

अगर तुलना करनी ही है, तो सबसे सार्थक तुलना अपने कल के व्यक्तित्व से होनी चाहिए। आज मैं कल से कितना बेहतर हूं? मेरे विचारों में कितना परिष्कार हुआ? मेरे व्यवहार में कितनी विनम्रता आई? मैंने क्रोध पर कितना नियंत्रण पाया? मैंने अपने कर्तव्यों को कितनी ईमानदारी से निभाया? मैंने किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए क्या किया?

उपलब्धि की परिभाषा यह नहीं कि हम किसी दूसरे से आगे निकल गए, बल्कि यह है कि हमने स्वयं को कल से बेहतर बना लिया। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव दूसरे से भिन्न होता है। आम के बीज से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह गुलाब की तरह खिले। जीवन में हर व्यक्ति की समय-तालिका अलग होती है। कोई बीस वर्ष की उम्र में सफल हो जाता है, कोई चालीस में, कोई साठ में और कोई शायद कभी उस अर्थ में सफल नहीं होता, जिसे समाज सफलता कहता है।

क्या इसका अर्थ यह है कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया? बिल्कुल नहीं। जीवन का मूल्य केवल उपलब्धियों से निर्धारित नहीं होता। तुलना का मूल कारण भीतर का असंतोष होता है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को केवल बाहरी पहचान से जोड़ना बंद कर देता है, तब तुलना की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। फिर दूसरे की सफलता ईर्ष्या नहीं, बल्कि प्रेरणा का कारण बनती है। दूसरे की प्रशंसा अपने अपमान का प्रतीक महसूस नहीं होती।

संतोष का अर्थ है प्रयास करते हुए भी परिणाम के प्रति भीतर से टूट न जाना। व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत करे, अपनी कमियों को दूर करे, ऊंचाइयों को प्राप्त करने का प्रयास करे, लेकिन किसी भी दशा में अपनी आत्मशांति को उपलब्धियों की शर्त न बनाए। जीवन को केवल उपलब्धियों की सूची बनाकर देखना ठीक उसी प्रकार है, जैसे किसी संगीत को केवल उसकी अवधि से मापना। किसी गीत की सुंदरता उसकी अवधि में नहीं, उसकी अनुभूति में होती है।

हमें समझना होगा कि सबसे कठिन प्रतियोगिता बाहर नहीं, भीतर है। क्रोध से धैर्य की ओर जाना, अहंकार से विनम्रता की ओर जाना, भय से विश्वास की ओर जाना, लोभ से संतोष की ओर जाना और स्वार्थ से सेवा की ओर जाना- यही वास्तविक विजय है। इस यात्रा में किसी दूसरे को हराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां विजेता और पराजित दोनों एक ही व्यक्ति होता है और वह है स्वयं हम।

खुशहाली के लिए जीवन की मापनी बदलने की आवश्यकता है। यह मापनी होनी चाहिए- चरित्र की, आत्मशांति की और आत्मतोष की। जीवन की सबसे सुंदर स्थिति वह है, जब मनुष्य दूसरों को देखकर यह नहीं सोचता कि 'मैं उनसे कितना पीछे हूं?', बल्कि स्वयं से यह प्रश्न करता है- 'मैं उनसे क्या सीख सकता हूं... क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर मनुष्य बना?' ये प्रश्न जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तुलना की मापनी बाहर से भीतर की ओर मोड़नी होगी।

अपने जीवन का मूल्यांकन हमें स्वयं करना होगा। मापनी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें मनुष्य किसी दूसरे से बड़ा नहीं, बल्कि अपने भीतर से बेहतर बनने का प्रयास करे। जहां सफलता का अर्थ किसी को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के अंधकार को थोड़ा कम करना हो। जहां समृद्धि का अर्थ केवल संग्रह नहीं, बल्कि बांटने की क्षमता हो। जहां ऊंचाई का अर्थ पद नहीं, दृष्टि की ऊंचाई हो। और जहां जीवन का अंतिम प्रश्न यह न हो कि 'मैं दूसरों से कितना आगे था?', बल्कि यह हो कि 'मैं अपने होने को कितना सार्थक कर पाया?' जब तुलना समाप्त होती है, तो आत्मबोध शुरू होता है और जब आत्मबोध शुरू हो जाता है, तब मनुष्य समझ पाता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, एक यात्रा है।

कोई परीक्षा नहीं, एक अनुभव है। कोई मापनी नहीं, एक साधना है। इस साधना में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि यात्रा पूरी होने पर हम स्वयं से कह सकें- 'मैंने किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं की, मैंने पूरी निष्ठा से स्वयं बनने का प्रयास किया। मैंने सदैव बाहरी परिस्थितियों एवं दूसरों की उपलब्धियों से अपने अंतर्मन को विरत रखते हुए आत्मोन्नति एवं आत्मपरिष्कार की चेष्टा की।' स्वयं से तुलना और फिर सार्थक प्रयास ही आत्मविकास का एकमात्र आधार है।

सार-समाचार

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खेल सकते हैं वाशिंगटन व रेड्डी

नई दिल्ली। भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, जिससे पहले ऑफ-स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर नितिश कुमार रेड्डी को फिटनेस हासिल कर चुके हैं। ये दोनों खिलाड़ी गुरुवार को टीम के साथ जुड़ेंगे। एक सूत्र ने बुधवार को 'आईएएनएस' को बताया, 'सुंदर और रेड्डी कुछ समय पहले ही पूरी तरह फिट हो गए थे। दोनों ने बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने फिटनेस टेस्ट और मैच सिमुलेशन पास कर लिए हैं।' उल्लेखनीय है कि वाशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण सुंदर श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज में नहीं खेल सके थे। वहीं, रेड्डी ने आखिरी बार जून में अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में खेला था, जिसके बाद उनके बाएं क्वाड्रिसेप्स की चोट बढ़ गई और वे आयरलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका के दौरे पर नहीं जा पाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में फील्डिंग के दौरान घुटने में लगी चोट के कारण जसप्रीत बुमराह खेल से बाहर हैं। ऐसे में उनके तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल होने के बारे में अभी कोई पक्की खबर नहीं है। सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर हर्षित राणा की भागीदारी पर भी संशय बना हुआ है, जो हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी राष्ट्रीय टीम के साथ नहीं जुड़ पाता, तो तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को आखिरी समय में टीम में शामिल किया जा सकता है। अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद भारतीय टीम एशियन गेम्स 2026 के लिए जापान रवाना होगी। टीम इंडिया 22 सितंबर को सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर मेजबान जापान के खिलाफ टी20 मैच खेलेगी, जिसके बाद 28 सितंबर को कोरोजी स्पोर्ट्स पार्क में एशियन गेम्स में अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने का अभियान शुरू करेगी।

'वह जल्द ही अपनी बेस्ट फॉर्म में लौटेंगे'

इंटर के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद जोस मोरिन्हो ने किया विनीसियस का बचाव

नई दिल्ली। रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी विनीसियस जूनियर को लेकर रियल मैड्रिड के मैनेजर जोस मोरिन्हो ने भरोसा जताया है। मोरिन्हो का कहना है कि विनीसियस जल्द ही अपनी पुरानी फॉर्म में लौटेंगे। चैंपियंस लीग में इंटर के खिलाफ रियल मैड्रिड की 2-1 की जीत के दौरान कुछ घरेलू दर्शकों ने विनीसियस के खिलाफ हूटिंग की थी। हालांकि, मोरिन्हो का मानना है कि वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और जल्द ही अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से आलोचकों का जवाब देंगे। बुधवार को सैंटियागो बर्नबेउ में 87वें मिनट में विनीसियस को सब्स्टीट्यूट किया गया, जिससे कुछ समर्थक उनके प्रदर्शन से

नाराज दिखे। ब्राजील का यह खिलाड़ी इंटर के मजबूत डिफेंस के सामने कुछ खास प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहा। हालांकि, मोरिन्हो ने विंगर की आलोचना करने से इनकार किया और इसके बजाय टीम के लिए उनकी मेहनत की तारीफ की। मैच के बाद मोरिन्हो ने पत्रकारों से कहा, 'वह अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं हैं, और उन्हें यह पता है, लेकिन वह उस विनीसियस जैसा बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो मैच का नतीजा तय करते हैं। अपनी बेस्ट फॉर्म में न होने के बावजूद वह पहले से कहीं अधिक मेहनत कर रहे हैं।'

पुर्तगाली मैनेजर ने थकान को भी एक कारण बताया जिसकी वजह से विनीसियस मैच के आखिर में डिफेंस में अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, 'जब वह पीछे आकर डिफेंस नहीं कर पाए, तो उसकी वजह थकान थी। मुझे इसकी बहुत कद्र है। मैं विनीसियस का बहुत सम्मान करता हूं। वह समय जरूर आएगा जब वह मैच का नतीजा तय करेंगे और हमें जीत दिलाएंगे।'

मोरिन्हो ने विनीसियस के प्रदर्शन की आलोचना का बचाव करते हुए इंटर की तकनीकी रणनीति के खिलाफ रियल मैड्रिड के अटैकर्स को हुई मुश्किलों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, 'अगर वह मेहनत करते हैं, तो उन्हें हमेशा मेरा समर्थन मिलेगा। उन्होंने टीम के लिए बहुत मेहनत की। ऐसी टीम के खिलाफ खेलना विंगर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है जो पीछे तीन डिफेंडर और विंग-बैक का इस्तेमाल करती है।'

रियल मैड्रिड के बॉस का मानना ?

जूनियर विमेंस हॉकी एशिया कप: शान से सेमीफाइनल में पहुंचीं भारत की बेटियां

पाकिस्तान को 19-0 से रौंदा

मोकी (चीन)। भारतीय टीम ने विमेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल का टिकट भी हासिल कर लिया है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने मैच की शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया। टीम को पहला गोल करने में सिर्फ सात मिनट लगे, जब पूजा साहू ने गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। दो मिनट बाद रोशनी ऐंड ने भारत

की बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार अटैक किया, जिससे पाकिस्तान की टीम पर दबाव बढ़ता चला गया। अगले पांच मिनट में भारत ने चार और गोल दाग दिए। तनुश्री दिनेश काडू ने 11वें मिनट में, सुखवीर कौर ने 13वें मिनट में और सानिका चंद्रकांत माने ने भी 13वें मिनट में गोल किया।

मधु सिदार और गीता यादव ने भी गोल कर टीम की बढ़त और बढ़ा दी। वहीं, सानिका माने ने 23वें मिनट में अपना दूसरा गोल करके भारत की मजबूत स्थिति को और मजबूत कर दिया। भारत ने पहले हाफ में अपना दबदबा पूरी तरह बनाए रखा। तनुजा टोप्पो और पूजा मलिक ने गोल करके टीम की बढ़त को और मजबूत किया।

इसके बाद 33वें मिनट में पूर्णिमा यादव ने भी गोल दागा, जिससे भारत ने हाफ-टाइम तक 10-0 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली।

दूसरे हाफ की शुरुआत के बाद भी भारतीय टीम ने आक्रामक खेल जारी रखा। 39वें मिनट में मधु सिदार ने एक और गोल किया और एक मिनट बाद सुप्रिया ने भी मैच का अपना पहला गोल दागा। इसके बाद पूजा मलिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49वें और 51वें मिनट में लगातार दो गोल किए और अपनी हैट्रिक पूरी की। भारत ने पूरे मैच में पाकिस्तान को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।

कृष्णा शर्मा और बिनिमा धन ने भी गोल किए, जिससे टीम की बढ़त लगातार बढ़ती गई। सुप्रिया ने 54वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागा, जबकि रोशनी ने मैच के आखिरी मिनट में गोल करके अपना दूसरा गोल पूरा किया और भारत की शानदार जीत पर मुहर लगा दी। भारत की यह 19-0 की बड़ी जीत कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि टीम ने ग्रुप चरण में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। भारत ने जापान, मलेशिया और साउथ कोरिया जैसी मजबूत टीमों को हराकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया था।

अब भारतीय टीम सेमीफाइनल में साउथ कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से भिड़ेगी। मौजूदा चैंपियन भारत लगातार तीसरी बार जूनियर महिला एशिया कप का खिताब जीतने से सिर्फ दो जीत दूर है। टीम ने 2023 और 2024 में भी यह ट्रॉफी अपने नाम की थी।

जूनियर एशिया कप हॉकी

अनमोल एक्का के छह गोल की मदद से भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में पहुंची

मोकी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने बुधवार को यहां अपने आखिरी पूल ए मैच में चीनी ताइपे को 15-0 से आसानी से हराकर एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत की तरफ से कप्तान कप्तान अनमोल एक्का ने छह गोल किए। एक्का ने सभी गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए। एक्का के गोलों की वजह से हीं भारत ने बिना गोल वाले शुरुआती क्वार्टर को एकतरफा मुकाबले में बदल दिया। इस जीत से भारत तीन जीत और एक ड्रॉ से 10 पॉइंट्स के साथ पूल ए में टॉप पर पहुंच गया। मैच में भारत ने गेंद पर दबदबा बनाए रखा और शुरुआती 15 मिनट में कई मौके बनाए, लेकिन चीनी ताइपे के मजबूत डिफेंस को भेद नहीं पाया। आखिरकार 17वें मिनट में

सफलता मिली जब आर्यन जेस ने पहला गोल किया, और एक मिनट बाद प्रभदीप सिंह ने बढ़त दोगुनी कर दी। 22वें मिनट में गुरसेवक सिंह ने स्कोर 3-0 कर दिया, जिसके तीन मिनट बाद एक्का ने अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर गोल में बदला। अर्जुन संतोष हरगुडे ने 28वें मिनट में एक और गोल किया, और कुछ ही देर बाद एक्का ने फिर गोल किया, जिससे भारत हाफ-टाइम में 6-0 की बढ़त के साथ गया।

तीसरा क्वार्टर पूरी तरह से भारत के नाम रहा। एक्का ने अपनी हैट्रिक पूरी करने के लिए दो शुरुआती पेनल्टी कॉर्नर गोल में बदले और फिर एक और गोल करके अपनी संख्या चार कर ली। अजीत यादव ने भी 35वें मिनट में गोल किया, जिसके बाद एक्का ने 45वें मिनट में फिर से गोल करके अपना स्कोर पांच कर दिया और भारत को डबल फिगर में पहुंचा दिया।

आखिरी क्वार्टर में हरपाल ने 48वें मिनट में गोल किया, जिसके तीन मिनट बाद एक्का ने एक और सफल पेनल्टी कॉर्नर के साथ अपना शानदार छह गोल का आंकड़ा पूरा किया। हरपाल ने इसके तुरंत बाद अपना दूसरा गोल किया, जबकि आर्यन जेस ने मैच का अपना दूसरा गोल करके भारत को 15-0 से जीत दिलाई।

एशियन गेम्स 2026

जेमिमा की जगह प्रतिका हुई भारतीय टीम में शामिल

नई दिल्ली। जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में टॉप-ऑर्डर की बल्लेबाज प्रतिका रावल को चोटिल जेमिमा रोड्रिग्स की जगह शामिल किया गया है। जेमिमा, जो भारत के मिडिल ऑर्डर की अहम खिलाड़ी हैं अभी भी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रही हैं। उन्हें यह चोट पिछले महीने की शुरुआत में 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में 'सदर्न ब्रेव' के लिए खेलते हुए लगी थी। इस चोट के कारण जेमिमा दुबई में चल रहे महिला एशिया कप 2026 से भी बाहर हो गई थीं। जब एशिया कप टीम में जेमिमा की जगह प्रतिका को शामिल करने की घोषणा की गई थी, तब उसके बाद होने वाले एशियन गेम्स के लिए उनकी जगह लेने वाली खिलाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने बुधवार को 'आईएएनएस' को बताया, 'प्रतिका एशियन गेम्स 2026 में जेमिमा रोड्रिग्स की जगह जापान जाएंगी। एशियन गेम्स के लिए सौंपी गई 15 सदस्यीय टीम में उनका नाम शामिल है।'

प्रतिका ने दुबई में चल रहे एशिया कप में अपना टी20 इंटरनेशल डेब्यू किया और भारतीय टीम मैनेजमेंट ने उन्हें नंबर तीन पोजीशन पर खेलने के लिए चुना। टूर्नामेंट के लीग स्टेज में प्रतिका ने 22, 10 और 4 रन बनाए हैं। एशिया कप के लिए भारतीय टी20 इंटरनेशनल टीम में उन्हें अचानक तब बुलाया गया जब वह इंग्लैंड में 'वन डे कप' में 'वार्विकशायर' के लिए खेलने की तैयारी कर रही थीं। हाल ही में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने से पहले प्रतिका ने नवंबर 2024 के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी टी20 मैच नहीं खेला था, महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान उनके टखने में चोट लग गई थी। इस चोट की वजह से उन्हें लंबे समय तक मैदान से बाहर रहना पड़ा और वह काफी समय तक क्रिकेट नहीं खेल सकीं।

उस चोट के कारण प्रतिका महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) का 2026 एडिशन भी नहीं खेल पाईं। उन्हें पिछले साल नई दिल्ली में हुए प्लेयर ऑक्शन में यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख रुपये में खरीदा था। भारतीय टीम मैनेजमेंट को उम्मीद होगी कि रावल मिडिल ऑर्डर में जल्द ही अपनी लय हासिल कर लेंगी, क्योंकि गुरुवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होना है। एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता 17 से 22 सितंबर तक होगी।

एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कामलिनी (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह, एन. श्री चरणी और नंदिनी शर्मा।

वनडे रिकॉर्ड: डेब्यू मैच में हरमन ने जड़े 150 रन

हमवतन खिलाड़ी के 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' की बराबरी

विंडहोक। साउथ अफ्रीका के 24 वर्षीय बल्लेबाज जॉर्डन हरमन वनडे डेब्यू मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में संयुक्त रूप से 'नंबर-1' बन गए हैं। बाएं हाथ के सलामी

बल्लेबाज ने बुधवार को नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर नामीबिया के खिलाफ 126 गेंदों में 3 छक्कों और 17 चौकों के साथ 150 रन जड़े। इसी के साथ हरमन ने हमवतन मैथ्यू ब्रीत्जके के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जिन्होंने 10 फरवरी 2025 को न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे फॉर्मेट में डेब्यू करते हुए 148 गेंदों में 16 बाउंड्री के साथ 150 रन की पारी खेली थी। पुरुषों की इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के डेसमंड हेन्स (148 बनाम ऑस्ट्रेलिया) तीसरे और अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज (127 बनाम आयरलैंड) चौथे स्थान पर हैं। भारत की तरफ से केएल राहुल डेब्यू वनडे मैच में शतक लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 348 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने महज 27 के स्कोर पर कॉनर एस्टरहुइजेन (10) का विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद हरमन ने टोनी डी जोरजी के साथ दूसरे विकेट के लिए 166 गेंदों में 190 रन जोड़कर टीम को दोहरे शतक के पार पहुंचा दिया।

जोरजी 84 गेंदों में 8 बाउंड्री के साथ 72 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद हरमन ने देवाल्ड ब्रेविस (33) के साथ तीसरे विकेट के लिए 58 रन जुटाए। टीम को हरमन के रूप में 275 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा, जिसके बाद 292 रन तक 5 विकेट गिर गए।

इसके बाद कॉर्बिन बॉश (नाबाद 39) ने जेसन स्मिथ (15) के साथ छठे विकेट के लिए 32 गेंदों में 41 रन जुटाकर टीम को तिहरे शतक के पार पहुंचाया। नामीबिया की तरफ से रूबेन ट्रम्पेलमैन ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि जेजे स्मिट और गेरहार्ड इरास्मस को 1-1 विकेट हाथ लगा।

दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज के तीन मुकाबले 9, 11 और 13 सितंबर को खेले जाएंगे। साउथ अफ्रीका सीरीज का पहला मैच जीतकर बढ़त हासिल करना चाहेगा।

35 महीने से वनडे क्रिकेट की 'बेताज बादशाह' टीम इंडिया, टी20 में भी हुकूमत कायम

नई दिल्ली। वनडे क्रिकेट में भारत का वर्चस्व लगातार कायम है। 50 ओवर के फॉर्मेट में पिछले 35 महीनों से दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम भी भारत से नंबर एक का ताज नहीं छिन सकी है। सिर्फ वनडे ही नहीं, बल्कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी टी20 में भी भारत का दबदबा लगातार बना हुआ है। वनडे क्रिकेट में भारतरीय टीम की बादशाहत सितंबर 2023 से कायम है। भारत ने पाकिस्तान से नंबर एक की कुर्सी छीनी थी और उसके बाद से किसी भी टीम को इस पोजीशन के आसपास तक नहीं भटकने दिया है। भारतीय टीम के अभी कुल 116 रेटिंग प्वाइंट्स हैं। भारत के बाद फिलहाल आईसीसी की ताजा रैंकिंग में न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है, जिसके कुल रेटिंग प्वाइंट 109 हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया 102 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है। 2023 से लेकर अब तक 50 ओवर के फॉर्मेट में भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। 2023 में टीम इंडिया ने कुल 35 वनडे मैच खेले और इस दौरान 27 मुकाबलों में जीत हासिल की, जबकि महज 7 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। साल 2024 में भारतीय टीम ने सिर्फ 3 ही वनडे मुकाबले खेले। इस दौरान टीम को 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, तो एक मुकाबला टाई रहा।

टीम इंडिया के लिए साल 2025 वनडे फॉर्मेट में बेमिसाल रहा। साल की शुरुआत में ही भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब पर कब्जा जमाते हुए अपनी बादशाहत साबित की। 2025 में भारत ने कुल मिलाकर 14 वनडे मुकाबले खेले और टीम को 11 में जीत नसीब हुई। वहीं, सिर्फ 3 ही मैचों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। भारत का जीत प्रतिशत 78.57 का रहा। साल के आखिरी में बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के हाथों से वनडे टीम की कमान लेकर शुभमन गिल के हाथों में सौंपी। गिल की कप्तानी में भले ही टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर वनडे सीरीज में हार मिली, पर टीम का प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा।

साल 2026 में भारत ने अभी तक कुल 9 वनडे मैच खेले हैं और इस दौरान टीम को 5 में जीत, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान भारत को इंग्लैंड की सरजमीं पर वनडे सीरीज गंवानी पड़ी। हालांकि, नए-नवेले कप्तान गिल की अगुवाई में भारत ने इस फॉर्मेट में हर बड़ी टीम को कड़ी टक्कर जरूर दी है।

टी20 में भी भारत का दबदबा लगातार कायम रखा है। भारतीय टीम फरवरी 2022 से क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में जुलाई 2026 तक नंबर वन रही। इसके बाद इंग्लैंड के हाथों पांच मैचों की टी20 सीरीज 0-4 से गंवाने के बाद टीम की 1600 दिनों से चली आ रही बादशाहत कुछ दिनों के लिए इंग्लिश टीम ने खत्म की। हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में बड़ी जीत के साथ ही भारत ने एक बार फिर टी20 के किंग का ताज पहन लिया।

टी20 फॉर्मेट में नंबर वन रहते हुए भारत ने लगातार दो बार टी20 विश्व कप के खिताब को अपने नाम किया। 2024 में रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में टीम को चैंपियन बनाया, तो 2026 में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी। भारत पहला ऐसा देश बना, जिसने सफलतापूर्वक अपने खिताब का बचाव किया और अपने ही घर में टी20 वर्ल्ड कप जीता।

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक अन्नपूर्णा गुप्ता द्वारा भास्कर प्रिंटिंग प्रेस प्लांट नं. 535 एवं 1272, लालगुटवा रातू पुलिस स्टेशन रांची में मुद्रित तथा विजय जनरल स्टोर, हिनू चौक रांची-834002 से प्रकाशित समस्त दिवानी विवाद न्यायोचित एवं दंडित परिवादों के लिए न्यायाधिकारी रांची न्यायालय में रहेगा। पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के जिम्मेदार। **प्रधान संपादक**-अन्नपूर्णा गुप्ता, कार्यालय नं.0651-2253830,मो.9471717919, 7895244551 ईमेलः alagpahchan@gmail.com, www.alagpahchan.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन 2013 JHAHINO0575 RNI No.JHAHIN(2013) 66670